आज का विचार

वक्त तो गुजर ही जाता है, चाहे जैसा भी हो, याद रह जाता है तो बस अच्छे बुरे वक्त में अपनों का रवैया।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । मंगलवार, 24 मार्च, 2026 वर्ष 24, अंक 71, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

अगर शहीद-ए-आजम भगत सिंह भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश के हालात आज कुछ और होते: भगवंत मान

शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी, पर भाजपा सरकार ने नहीं मानी: मुख्यमंत्री

सिटी दर्पण संवाददाता

हुसैनीवाला (फिरोजपुर)

फिरोजपुर के हुसैनीवाला में शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहीदों के सम्मान में उनके सपनों का रंगला पंजाब बनाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए यहां ऐतिहासिक राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया और 24.99 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले हुसैनीवाला विरासत परिसर का शिलान्यास किया गया।

देश के महान क्रांतिकारियों की गौरवशाली विरासत को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह अवसर केवल उन वीरों के बलिदान को याद करने का ही नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के दृढ़ संकल्प को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का भी है। उन्होंने शहीदों की महान सोच के अनुरूप पंजाब और देश की सेवा करने के अपने संकल्प को दोहराया और साथ ही इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को अब तक भारत रत्न (सर्वोच्च सम्मान) न दिए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आजादी के शुरूआती वर्षों में यदि देश की बागडोर ऐसे साहसी युवाओं के हाथों में होती तो भारत की तस्वीर कुछ और ही होती।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, इस देश के लालची और स्वार्थी नेताओं ने जीवित रहते हुए अपने नाम पर स्टेडियम बनवा लिए, लेकिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव जैसे सच्चे शहीदों को सम्मानित करने के लिए आज तक कोई आगे नहीं आया।

मुख्यमंत्री ने कहा, इन महान क्रांतिकारियों ने कम उम्र में अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन आजादी के बाद सत्ता के लालचियों ने कुर्सी पर कब्जा कर लिया और खून बहाकर हासिल की गई आजादी का श्रेय खुद ले लिया, जिसके लिए उन्होंने कभी संघर्ष भी नहीं किया।

उन्होंने कहा, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव और शहीद-ए-आजम भगत सिंह को याद करने के लिए केवल फूल ही रह गए, जबकि अन्य लोग आजादी की विरासत का झूठा दावा कर प्रमुख बन गए। मुख्यमंत्री ने कहा, उन महान योद्धाओं को चुप कराने के लिए ही उन्हें जल्द फांसी दी गई थी, क्योंकि लोग उनके निडर विचारों के पीछे इकट्ठा होने लगे थे।

महंगी कीमत पर मिली आजादी का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हमारी आजादी कितनी महंगी थी– विभाजन के दौरान लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों लोग विस्थापित हुए। उन्होंने आगे कहा, हमारे बुजुर्गों ने बहुत बलिदान दिए, लेकिन सत्ताधारी इस पीड़ा को समझने में असफल रहे हैं, क्योंकि उन्हें शहीदों की कुर्बानियों से बना तैयार देश विरासत में मिला।

पश्चिम एशिया संकट को मोदी ने चिंताजनक बताया, राष्ट्रीय एकजुटता का किया आह्वान

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष को चिंताजनक बताते हुए कहा कि यह संकट भारत के लिए आर्थिक, सुरक्षा और मानवीय स्तर पर गंभीर चुनौतियां पैदा कर रहा है। उन्होंने संसद और देश से इस मुद्दे पर एकजुट होकर प्रतिक्रिया देने का आान किया, ताकि वैश्विक मंच पर भारत की स्पष्ट और मजबूत आवाज पहुंच सके। प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया सैन्य संघर्ष और इसकी वजह से भारत के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले तीन सप्ताह से अधिक समय से जारी यह संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। सरकार इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और विदेश मंत्री तथा पेट्रोलियम मंत्री द्वारा संसद को समय-समय पर जानकारी दी जा चुकी है।

मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां से देश की बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति होती है, वहीं यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार मार्गों के लिहाज से भी अहम है। खाड़ी देशों में लगभग एक करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं, जबकि समुद्री जहाजों में भी बड़ी संख्या में भारतीय क्रू सदस्य कार्यरत हैं। ऐसे में इस संकट का भारत पर प्रभाव स्वाभाविक रूप से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 3.75 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। ईरान से करीब 1000 भारतीयों को निकाला गया है, जिनमें 700 से अधिक मेडिकल छात्र शामिल हैं। विदेशों में स्थित भारतीय मिशन 24 घंटे काम कर रहे हैं और प्रभावित नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं।

ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते खतरे के बावजूद सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि भारत ने ऊर्जा आयात के स्रोतों को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक विविधीकृत किया है। साथ ही देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने एलपीजी की घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी है और उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग, रेलवे विद्युतीकरण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे कदमों से तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है। भारत अब पेट्रोल में लगभग 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है।

कृषि क्षेत्र पर संभावित प्रभाव का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है और किसानों को किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाया है और आयात के स्रोतों को भी विविध बनाया है। साथ ही नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊर्जा और बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पावर प्लांट्स में पर्याप्त कोयला भंडार है और सरकार हर स्तर पर निगरानी कर रही है। भारत ने लगातार दूसरे वर्ष 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावॉट से अधिक हो चुकी है, जिसमें सौर ऊर्जा का बड़ा योगदान है। कूटनीतिक प्रयासों पर जोर देते हुए मोदी ने कहा कि भारत शुरू से ही शांति और संवाद का पक्षधर रहा है। मोदी ने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देश के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ दो राउंड फोन पर बातचीत कर तनाव कम करने और संघर्ष समाप्त करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिक और वाणिज्यिक ढांचे पर हमलों का विरोध किया है और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर बल दिया है। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए देश को धैर्य, संयम और एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत ने पहले भी कठिन परिस्थितियों का सामना एकजुट होकर किया है।

ओम बिरला ने श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात, सहयोग और संबंधों पर दिया जोर

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रीलंका की संसद की मूलभूत ढांचा और सामरिक मुद्दों पर निगरानी समिति के अध्यक्ष एसएम मारिक्कर के नेतृत्व में आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर संसदीय सहयोग, द्विपक्षीय संबंधों और मूलभूत ढांचा क्षेत्र में साझेदारी को विस्तार देने पर जोर दिया।

संसद भवन में मुलाकात के दौरान ओम बिरला ने कहा कि भारत और श्रीलंका के रिश्ते केवल पड़ोसी देशों के नहीं हैं, बल्कि साझा संस्कृति और विरासत से जुड़े आत्मीय संबंध हैं। भारतीय संसद का बजट सत्र देश के विकास से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा का अवसर देता है, जहां सरकार के खर्च और नीतियों की गहन समीक्षा कर भविष्य की दिशा तय की जाती है।

लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय समितियों को मिनी संसद बताते हुए कहा कि इन समितियों में मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श कर ठोस और प्रभावी निर्णय तैयार किए जाते हैं। उन्होंने भारत-श्रीलंका संसदीय मैत्री समूह को द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा देने वाला कदम बताया और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

बिरला ने कहा कि यह संवाद दोनों देशों के संसदीय संबंधों को नई ऊंचाई देगा और साझा प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने मूलभूत संरचना के क्षेत्र में सहयोग विस्तार पर भी सहमति जताई।

पश्चिम बंगाल-असम में भाजपा की जीत तय, तमिलनाडु में भी राजग सत्ता में आएगा : प्रह्लाद जोशी

बागलकोट। केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ेगा, जबकि असम में भाजपा फिर से सत्ता में आएगी। इसके अलावा,

उन्होंने तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सत्ता में आने का भी भरोसा जताया। कर्नाटक के बागलकोट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार वीरन्ना चरंतीमठ के समर्थन में आयोजित रोड शो के दौरान उन्होंने यह बयान दिया। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इस राज्य में भी भाजपा के पक्ष में माहौल बन रहा है और पार्टी उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम में कट्टरपंथियों का खेल समाप्त हो रहा है। साथ ही कर्नाटक में तुष्टिकरण की राजनीति खत्म करने की जरूरत बताते हुए लोगों से कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने का आान किया। उन्होंने कहा कि चुनावों में भाजपा के पक्ष में लहर दिखाई दे रही है और जनता का समर्थन पार्टी के लिए मजबूत आधार बनेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाएं और सरकार के विकास कार्य भाजपा की जीत सुनिश्चित करेंगे।

मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार, एक संस्था हैं: शिवराज

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार प्रमुख के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार, एक संस्था हैं। दिन-रात काम करना और उनकी परिश्रम की परिकाष्ठा ने इसका एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि मन गर्व और आनंद से भर जाता है।

शिवराज ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी प्रधानमंत्री बने और इसके बाद देश के विकास के एक नए युग का प्रारंभ हुआ। मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। वो राष्ट्र के आराधक और जनता के सेवक हैं। यही उनके कार्यों की मूल प्रेरणा है। बीते दिनों की यादें ताजा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ था, बेहद सादगीपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार संपन्न हुआ और हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री मोदी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और वो रेलवे के उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर झंडी दिखा रहे थे। ये अपने आप में अद्भुत घटना है। उन्होंने कहा कि साल 2011, 2012, 2013 के वो काले दिन थे, जब चारों तरफ घोटालों का शोर सुनाई पड़ता था।

बेइमानी, भ्रष्टाचार घोटाले सब चरम सीमा पर थे। उन दिनों भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी। जनता हताश और निराश थी। निराशा के इस अंधकार में आशा और विश्वास के प्रतीक बनके निकले मोदी। देश में चारों तरफ सिर्फ मोदी-मोदी। शिवराज ने कहा कि एक जमाना था, जब निवेशकों को कहा जाता था कि गुजरात मत जाना। गुजरात कभी भयानक सूखे से जूझता था। नर्मदा का जल समुद्र में बह जाता था और सरदार सरोवर डैम वर्षों तक राजनीति में अटका रहा। फिर मोदी ने गुजरात के कायाकल्प का संकल्प लिया। उन्होंने प्रण लिया कि कैसे नर्मदा के पानी गुजरात की जनता के सूखे कंठों की प्यास बुझाए और कैसे खेतों में फसल लहलहाए। उन्होंने कहा कि वे मोदी को 35 वर्षों से जानते हैं। वे भारत माता के सच्चे उपासक और राष्ट्र के आराधक हैं।

वेयर हाउसिंग जिला प्रबंधक आत्महत्या केस में पंजाब के पूर्व मंत्री भुल्लर गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)

चंडीगढ़

पंजाब पुलिस ने अमृतसर में वेयरहाउस के जिला प्रबंधक के आत्महत्या मामले में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने यह कार्रवाई ऐसे समय में की, जब सोमवार को कई सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस केस की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। अमृतसर में बीते शनिवार को वेयरहाउसिंग के जिला प्रबंधक गगनदीप रंधावा ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के दौरान उन्होंने एक वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें पंजाब के तत्कालीन परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर समेत कई लोगों के नाम लिए गए। इसके बाद पंजाब पुलिस ने लालजीत भुल्लर, उनके पिता सुखदेव भुल्लर तथा निजी सचिव दिलबाग सिंह के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया। रविवार को पंजाब के सभी राजनीतिक दलों ने चंडीगढ़ में भुल्लर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इसी दौरान सोमवार को रंधावा आत्महत्या प्रकरण में पंजाब पुलिस ने लालजीत भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया।

अमृतसर के डीसीपी रविंदर पाल ने कहा कि फतेहगढ़ साहब पुलिस की मदद से लालजीत सिंह भुल्लर को मंडी गोबिंदगढ़ से गिरफ्तार किया है। भुल्लर को अमृतसर की अदालत में पेश किया जाएगा। लालजीत सिंह भुल्लर ने सोशल मीडिया (फेसबुक) पर पोस्ट डालकर दावा किया कि उन्होंने सरेंडर किया है।

इसी दौरान पंजाब के सांसदों ने आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करके इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग उठाई। कांग्रेस के 7 में से 4 सांसदों ने अमित शाह को इस संबंध में पत्र लिखा। इस पत्र पर जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला और पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी के हस्ताक्षर हैं। इसके साथ अकाली दल की बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी अलग से पत्र लिखकर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की है।

मुख्यमंत्री योगी ने की मेट्रो परियोजनाओं की समीक्षा, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य के दिए निर्देश

एजेंसी (हि.स.)

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश में संचालित मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को आधुनिक, सुगम और विश्वस्तरीय शहरी परिवहन व्यवस्था में देश का अग्रणी राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए निर्माण से लेकर संचालन तक हर स्तर पर दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और संबंधित विभागों के बीच नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मेट्रो केवल आवागमन का साधन नहीं है, बल्कि शहरों की अर्थव्यवस्था को गति देने और निवेश आकर्षित करने का मजबूत माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो परियोजनाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आय के नए स्रोत विकसित किए जाएं। स्टेशनों और परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियों जैसे मल्टीलेवल पार्किंग, रिटेल, फूड कोर्ट और ऑफिस स्पेस को बढ़ावा दिया जाए। विज्ञापन और डिजिटल ब्रांडिंग के अवसरों का अधिकतम उपयोग हो, तथा मेट्रो की भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का बेहतर ढंग से उपयोग किया जाए। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के माध्यम से बड़े स्तर पर राजस्व सृजन, भूमि मूल्य संवर्धन और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ताकि मेट्रो परियोजनाएं दीर्घकाल में आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि मेट्रो के साथ मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जाए, ताकि यात्रियों को घर से गंतव्य तक निर्बाध यात्रा मिल सके। इसके लिए मेट्रो स्टेशनों को सिटी बस, ई-रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित सेवाओं से जोड़ा जाए। तीनों शहरों में अतिरिक्त पार्किंग स्थलों के विकास, फीडर रूट के निर्धारण और निजी बस सेवाओं के समन्वय पर भी तेजी से काम करने को कहा गया। बैठक में लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि लखनऊ मेट्रो का लगभग 23 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर पूर्ण रूप से संचालित है। इसके विस्तार के अंतर्गत चारबाग से वसंत कुंज (कॉरिडोर-1बी, लगभग 11.16 किमी) को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले क्षेत्रों को आधुनिक कनेक्टिविटी मिलेगी। कानपुर मेट्रो परियोजना के कुल 32.4 किलोमीटर लंबे दोनों कॉरिडोर पर कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें लगभग 15 किलोमीटर सेक्शन पर संचालन प्रारंभ हो चुका है। शेष कार्य को मार्च 2027 तक पूरा करने की योजना है। आगरा मेट्रो की लगभग 29.4 किलोमीटर लंबी परियोजना में प्राथमिक सेक्शन (करीब 6.5 किमी) पर संचालन जारी है तथा कॉरिडोर-1 को जून 2026 तक और कॉरिडोर-2 को चरणबद्ध रूप से वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि मेट्रो सेवाओं का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और लखनऊ, कानपुर तथा आगरा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर यातायात का दबाव कम हुआ है और समय की बचत हो रही है। बेहतर परिचालन प्रबंधन और ऊर्जा दक्ष तकनीकों के उपयोग से संचालन लागत में नियंत्रण रखते हुए गैर-भाड़ा आय (नॉन-फेयर बॉक्स) जैसे विज्ञापन, रिटेल, ब्रांडिंग और स्टेशन परिसरों के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 में लगभग 222 करोड़ रुपये की आय दर्ज की गई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। तकनीकी गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जहां भी आवश्यक हो, नई तकनीकों का उपयोग कर कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। आमजन को बेहतर, सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता रहे।

हिमाचल में कानून के दायरे में आएंगे स्पा सेंटर, नई पॉलिसी बनाएगी सुक्खू सरकार

जनवरी से शुरू की गई किसान भवन, निरीक्षण कुटीर और अन्य भवनों की ऑनलाइन बुकिंग

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

हिमाचल प्रदेश में चल रहे स्पा सेंटरों को जल्द कानून के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार इन्हें नियमित करने के लिए नई पॉलिसी और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाएगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सोमवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान विधायक राजेश गौड़ के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में स्पा सेंटर लेबर लॉ के तहत पंजीकृत होते हैं और कानून के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जाती है। सरकार अब स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के साथ मिलकर ऐसी नीति तैयार करेगी, जिससे स्पा सेंटरों में चल रही गतिविधियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द दोनों विभागों की बैठक बुलाई जाएगी। मंत्री ने लोगों से अपील की कि यदि कहीं गलत गतिविधियों की जानकारी मिले तो इसकी शिकायत पुलिस को करें। जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग से 5 लाख की कमाई

विधानसभा में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जल शक्ति विभाग के 81 रेस्ट हाउस, किसान भवन, निरीक्षण कुटीर और अन्य भवनों की ऑनलाइन बुकिंग इस साल जनवरी से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इससे अब तक विभाग को लगभग 5 लाख रुपये की आय हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के तहत करीब 27 करोड़ रुपये की लागत से रेस्ट हाउस बनाए गए थे। राज्य सरकार इस राशि को जारी करवाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है। नदियों और खड्डों के चैनलाइजेशन के लिए केंद्र की प्राथमिकता जरूरी उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नदियों और खड्डों के चैनलाइजेशन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकता बदलना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि छौंछ खड्ड के चैनलाइजेशन के लिए वर्ष 2019 में 26 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, लेकिन इसके बाद राशि जारी नहीं हुई। अब इस परियोजना की लागत बढ़कर लगभग 300 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में ब्यास नदी, चक्की खड्ड और अन्य खड्डों में बाढ़ से बचाव के लिए तटीकरण और सुरक्षा परियोजनाएं तैयार करने का मामला फिलहाल विचाराधीन है।

ढोल-नगाड़ों की तान पर झूमते देवताओं के साथ हुआ राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेले का शुभारंभ

- जवाहर पार्क में ध्वज फहराकर मेले का औपचारिक उद्घाटन हुआ

एजेंसी (हि.स.)

मंडी

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के विधायक रघुबीर सिंह बाली ने मंडी जिला के सुंदरनगर में राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने शुकदेव वाटिका में देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की तथा शुकदेव वाटिका से जवाहर पार्क तक निकाली गई भव्य शोभायात्रा में भाग लिया। इसके पश्चात जवाहर पार्क में मेले का ध्वज फहराकर मेले का औपचारिक उद्घाटन किया।

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए आर.एस. बाली ने कहा कि प्रदेश के मेलों की समृद्ध परंपरा में रियासतकाल से मनाया जा रहा सुकेत देवता मेला विशेष स्थान रखता है। शुकदेव ऋषि की तपोस्थली में आयोजित यह मेला देव आस्था और परंपरा का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि मेले हमारी समृद्ध संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं, जो आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहार अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। सुकेत देवता मेला प्राचीन काल से मनाया जा रहा है, जिसमें सुकेत रियासत के विभिन्न देवी-देवता भाग लेते हैं। इस बार 180 वर्षों के बाद उपमंडल करसोग के महोग क्षेत्र से गढ़पति नाग चवासी सिद्ध पैदल सफर तय कर मेले में पधारे हैं। आर.एस. बाली ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं प्रदेश सरकार की ओर से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देवी-देवताओं के साथ हजारों श्रद्धालुओं की भागीदारी हिमाचल की परंपरा और संस्कृति को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि इन परंपराओं को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना आवश्यक है, क्योंकि यही हमारी पहचान का आधार हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में वर्षभर उत्सव और त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जो हमारी आस्था, मूल्यों और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करते हैं। मेले और त्योहार समाज में नई ऊर्जा का संचार करते हैं और सभी को इनमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

बजट जनता के साथ धोखा : डॉ. बिंदल

एजेंसी (हि.स.)

नाहन

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने आज सोमवार को हरिपुरधार में श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के तीनों भाजपा मण्डल के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। डॉ. बिंदल ने कहा कि इस बैठक में विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं मंथन हुआ। इसके अलावा विभिन्न जन-समस्याओं पर भी बैठक में गंभीर चिंतन हुआ। डॉ. बिंदल ने कहा कि मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुखु द्वारा प्रस्तुत बजट हिमाचल को पीछे ले जाने वाला यानी बैक गियर बजट है। उन्होंने कहा कि 4000 करोड़ रुपये की कटौती, गारंटियों पर धोखा और विकास योजनाओं पर ब्रेक यह सब इस बजट की मुख्य विशेषताएं हैं और ऐसा बजट हिमाचल के इतिहास में कभी प्रस्तुत नहीं हुआ है। डॉ. बिंदल ने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों से कांग्रेस सरकार केंद्र की मोदी सरकार को कोसने में लगी रही है और चौथे बजट की शुरूआत भी उसी मानसिकता के साथ की गई। जबकि सच्चाई यह है कि हिमाचल प्रदेश में चल रही अधिकांश योजनाएं केंद्र प्रायोजित हैं और प्रदेश का विकास केंद्र सरकार के सहयोग से ही आगे बढ़ रहा है। डॉ. बिंदल ने कहा कि बजट में कानून व्यवस्था को सुधारने, बढ़ते माफिया राज पर नियंत्रण, अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता और बंद किए गए संस्थानों को पुनः खोलने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है।

शिमला में एक महीने से लापता 22 वर्षीय युवक सोलन से सुरक्षित बरामद

शिमला। शिमला जिले के जुन्गा क्षेत्र से करीब एक महीने पहले लापता हुए 22 वर्षीय युवक को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। युवक 20 फरवरी 2026 से घर से लापता था और उसके परिजनों ने इस संबंध में 17 मार्च 2026 को पुलिस चौकी जुन्गा में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने युवक की तलाश के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस के अनुसार जुन्गा तहसील के रहने वाले स्वर्ण सिंह मेहता ने अपने बेटे निशांत उर्फ निशु के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिजनों ने बताया था कि युवक घर से केवल 300 रुपये लेकर पेट दर्द के इलाज के लिए सिविल अस्पताल चायल जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटा। युवक अपने साथ कोई मोबाइल फोन भी नहीं ले गया था, जिससे उसकी तलाश और कठिन हो गई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उसे आखिरी बार सोलन बस स्टैंड के आसपास देखा गया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने लगातार अलग-अलग स्थानों पर युवक की तलाश जारी रखी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि लापता युवक सोलन की सब्जी मंडी क्षेत्र में कबाड़ का काम कर रहा है।

शिमला में नशे के कारोबार से जुड़ी संपत्तियों की होगी जांच

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

नशे के कारोबार से अर्जित सम्पत्तियों की प्रशासन जांच करेगा। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जिला स्तरीय मासिक एनकॉर्ड समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की संपत्तियों की पहचान कर उनकी जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह बैठक सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी एसडीएम और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि शिमला जिला पुलिस नशे के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है और हाल ही में एक बड़े नशा गिरोह का भी पदार्फाश किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि पटवारी अपने-अपने क्षेत्रों में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की जानकारी एकत्र कर एसडीएम को भेजें, ताकि ऐसे मामलों की निगरानी कर संपत्तियों की जांच की जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। उपायुक्त ने कहा कि नशे के कारोबारियों की संपत्तियों की जांच में पुलिस को राजस्व विभाग और अन्य विभागों का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नशे के खिलाफ चल रही जागरूकता गतिविधियों का रिकॉर्ड भी व्यवस्थित तरीके से रखा जाए और सभी विभाग मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं। उन्होंने बताया कि ड्रग फ्री हिमाचल मोबाइल ऐप के बारे में स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को जागरूक किया जाएगा, ताकि युवा वर्ग नशे के खिलाफ जागरूक हो और जरूरत पड़ने पर गुप्त रूप से सूचना भी दे सके। इस ऐप के जरिए दी गई सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रहती है। उपायुक्त ने कहा कि पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग को अवैध शराब और उसके भंडारण पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

संक्षिप्त-समाचार

सड़क निर्माण की मशीनों से डीजल चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार

शिमला। शिमला जिले के झाकड़ी थाना क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान निर्माण कंपनी की मशीनों से डीजल और उपकरण चोरी होने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह मामला 17 और 18 मार्च की मध्यरात्रि को ज्यूरी-सराहन मार्ग पर सामने आया था, जहां सड़क निर्माण में लगी मशीनरी से चोरी की घटना हुई थी। इस घटना के बाद 20 मार्च को पुलिस थाना झाकड़ी में भारतीय न्याय संहिता (इठर) की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान मौके पर खड़ी मशीनों जेसीबी, पोकलेन और टिप्पर से अज्ञात लोगों ने करीब 500 लीटर डीजल, तीन ग्रीस गन और अन्य उपकरण चोरी कर लिए थे। चोरी गए सामान की कुल कीमत लगभग 1 लाख 71 हजार रुपये आंकी गई थी। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस टीम ने ज्यूरी, बठारा, घराट और मझगांव क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से निरीक्षण किया। फुटेज में कुछ संदिग्ध वाहनों और लोगों की गतिविधियां वारदात के समय आसपास के क्षेत्रों में देखी गईं। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और आरोपी की पहचान गौरव नेगी निवासी गांव सनारसा के रूप में की।

लापता युवक का खेत में दबा मिला शव, तीन दोस्तों पर हत्या का आरोप, फरार

शिमला। शिमला जिले के सुन्नी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले लापता हुए 25 वर्षीय युवक के मामले में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस युवक की कई दिनों से तलाश की जा रही थी, उसका शव अब बसन्तपुर के पास एक खेत के कोने में गड्ढे में दबा हुआ मिला है। पुलिस का कहना है कि युवक की हत्या उसके साथ रहने वाले तीन साथियों ने ही की और वारदात के बाद वे फरार हो गए हैं। इस घटना के सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान राम प्रवेश राम उर्फ कुटुम्ब (25) निवासी जिला मोतिहारी, बिहार के रूप में हुई है। वह अपने तीन अन्य साथियों अरुण, विकेश कुमार और महेश कुमार (सभी 22 वर्ष) के साथ शिमला जिले के बसन्तपुर क्षेत्र में किराये के कमरे में रहकर भवन निर्माण कार्य करता था। ये सभी मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और मजदूरी का काम करते थे। मामले की शुरूआत 15 मार्च को हुई थी, जब मृतक के पिता चतुरी राम निवासी जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) ने थाना सुन्नी में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि उनका बेटा अपने तीन साथियों के साथ लापता है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बसन्तपुर में उनके किराये के कमरे की तलाशी ली, लेकिन कमरे में कोई मौजूद नहीं मिला। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया और जांच शुरू कर दी।

कश्मीर घाटी में ईंधन या एलपीजी की कोई कमी नहीं,पर्याप्त भंडार उपलब्ध : संभागीय आयुक्त

श्रीनगर। संभागीय आयुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग ने सोमवार को कहा कि घाटी में ईंधन या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और स्थिति पर कई स्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए संभागीय आयुक्त ने कहा कि कश्मीर भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है और लगभग 10 से 15 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि भंडार की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन फिलहाल हमारे पास पर्याप्त उपलब्धता है। किसी भी प्रकार की रुकावट न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए संभागीय और जिला स्तर पर निरंतर निगरानी की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति भी स्थिर है और जमाखोरी, कालाबाजारी या अधिक कीमत जैसी अनियमितताओं को रोकने के लिए जिला स्तरीय समितियां तेल विपणन कंपनियों पर कड़ी निगरानी रख रही है। गर्ग ने कहा कि जिला और संभागीय स्तर पर नियंत्रण कक्ष आपूर्ति और वितरण पर सक्रिय रूप से नजर रख रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग केंद्रीकृत प्रारूप में दैनिक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है, ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर काम कर रही टीमें समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन शिकायतों का सक्रिय रूप से समाधान कर रही हैं।

सीएम के मीडिया सलाहकार के बेटे पर हमले के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

शिमला। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे आर्यन चौहान पर गनपॉइंट पर हमले और लूट की कोशिश के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 48 वर्षीय चरणजीत सिंह निवासी मेन बाजार संजौली और 45 वर्षीय ताशी नेगी निवासी नारकंडा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनकी मंशा और आपराधिक पृष्ठभूमि की गहन जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार यह मामला 20 मार्च को दर्ज किया गया था, जब शिकायतकर्ता आर्यन चौहान, जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे हैं और नव विहार शिमला के निवासी हैं, ने थाना ढली में शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि तारापुर सड़क पर तीन संदिग्धों ने उनकी गाड़ी को रोककर फिरौती और लूटपाट करने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने उन्हें हथियार दिखाकर डराया-धमकाया और घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मौके का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान भौतिक, डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का

न्वोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा

संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।

संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

बजट से युवाओं को निराशा, औद्योगिक गलियारों में भी मायूसी: सन्नी शुक्ला

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

भारतीय जनता युवा मोर्चा के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष सन्नी शुक्ला ने प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए वर्ष 2026-27 के बजट को युवाओं और औद्योगिक विकास की उम्मीदों के विपरीत बताया है। उनका कहना है कि बजट में रोजगार बढ़ाने और औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए कोई ठोस योजना सामने नहीं आई है, जिससे प्रदेश के शिक्षित युवाओं में निराशा का माहौल है।

सन्नी शुक्ला ने सोमवार को कहा कि प्रदेश का युवा लंबे समय से सरकारी नौकरियों की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन हमीरपुर चयन आयोग के भंग होने के बाद से भर्ती प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी हुई है। हजारों पद खाली होने के बावजूद बजट में इन भर्तियों को दोबारा शुरू करने के लिए कोई स्पष्ट समयसीमा या योजना नहीं बताई गई। उनका कहना है कि कई परीक्षाओं के परिणाम भी लंबे समय से लंबित हैं और सरकार की चुप्पी से लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों को झटका लगा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियां नहीं बढ़तीं, तो युवाओं का भविष्य प्रभावित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जैसे बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन), काला अंब, पांवटा साहिब और ऊना को इस बजट में अपेक्षित महत्व नहीं मिला है। उनके अनुसार पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार बजट का आकार कम होने से औद्योगिक ढांचे और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि निवेश के अनुकूल माहौल मजबूत न होने से नए उद्योग राज्य में आने से हिचक रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी सीमित हो रहे हैं। सन्नी शुक्ला ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी चिंता जताई। उन्होंने पीएलएफएस के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर करीब 29.9 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

कठुआ में जनगणना 2027 फेज-1 की तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न

कठुआ। जिला प्रशासन कठुआ द्वारा जनगणना 2027 के फेज-1 (हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग जनगणना) के लिए आयोजित तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया। कार्यक्रम का आयोजन निदेशालय जनगणना संचालन, जम्मू-कश्मीर के दिशा-निदेर्शों के अनुसार किया गया, जिसका उद्देश्य जिला एवं चार्ज स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों की क्षमता को सुदृढ़ करना था। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान अधिकारियों को हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं, उनकी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही, उन्हें जनगणना प्रबंधन एवं प्रणाली और एचएलबीएस वेब एप्लिकेशन के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। यह प्रशिक्षण 16, 18 और 23 मार्च 2026 को विभिन्न सत्रों में आयोजित किया गया, ताकि जनगणना 2027 फेज-1 के सुचारू एवं प्रभावी संचालन के लिए सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं को कवर किया जा सके। जिला उपायुक्त कठुआ एवं प्रधान जनगणना अधिकारी राजेश शर्मा ने सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़ों के महत्व पर जोर देते हुए फील्ड स्तर के कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई। उन्होंने अधिकारियों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और पेशेवर ढंग से करने का आह्वान किया।

शिवसेना का शहीदी दिवस पर युवाओं को नशे से दूर रहने व राष्ट्र निर्माण का आह्वान

एजेंसी (हि.स.)

जम्मू

शहीदी दिवस के अवसर पर शिवसेना (यूबीटी) जम्मू-कश्मीर इकाई द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पत की गई।

पार्टी के प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रमुख मनीश साहनी ने कहा कि इन वीर सपूतों का बलिदान देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने अपनी जवानी और सपनों का बलिदान देकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी और भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहनी ने कहा कि इन क्रांतिकारियों का त्याग, साहस और देशभक्ति आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे केवल श्रद्धांजलि तक सीमित न रहें बल्कि इन महान वीरों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हुए एक मजबूत, आत्मनिर्भर और राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत भारत के निर्माण का संकल्प लें। जम्मू-कश्मीर के वर्तमान हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, नशे की प्रवृत्ति और युवाओं का भटकाव गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। जिस युवा के हाथों में तिरंगा होना चाहिए आज वही नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है।

कॉलेज में शहीद दिवस का आयोजन

एजेंसी (हि.स.)

हमीरपुर

शहीद दिवस के पावन अवसर पर मेरा युवा भारत हमीरपुर के तत्वावधान में त्रिशा बी.एड. कॉलेज में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया।

कार्यक्रम में कॉलेज की प्रिंसिपल पूनम भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसके उपरांत सभी उपस्थित जनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विद्यार्थियों के मध्य पदयात्रा और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने देशभक्ति, स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों के अद्वितीय बलिदान पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही शहीदों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक पदयात्रा भी निकाली गई, जिसमें विद्यार्थियों एवं स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पूनम भारद्वाज को शॉल, टोपी एवं पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी दीपमाला ने उपस्थित विद्यार्थियों को शहीद दिवस के महत्व, इसके ऐतिहासिक संदर्भ तथा देश के लिए शहीदों के अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थितजनों ने शहीदों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा देश की एकता, अखंडता एवं गौरव को बनाए रखने का संकल्प लिया।

मौसम | हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार

कई हिस्सों में मौसम खराब, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट

- गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर तेज आंधी और बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसी तरह 26 मार्च को भी कुछ इलाकों में आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। विभाग का कहना है कि 29 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं और बीच-बीच में वर्षा का दौर जारी रह सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च महीने में इस बार मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं।

महीने के पहले पखवाड़े में लंबे समय तक मौसम शुष्क रहने के कारण तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया था और कई स्थानों पर मई जैसी गर्मी महसूस की गई। इसके बाद 18 मार्च से मौसम में अचानक बदलाव आया और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी तथा निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हुआ। इस बदलाव के कारण प्रदेश में ठंडक लौट आई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि पिछले दो दिनों से राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है और धूप खिली हुई है। इसके बावजूद विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर-पश्चिम भारत की ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बदल सकता है। इस बीच प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो शिमला में आज न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में 11.5 डिग्री, भुंतर में 9.6 डिग्री, कल्पा में 2.6 डिग्री, धर्मशाला में 8.9 डिग्री, ऊना में 12.4 डिग्री, नाहन में 9.5 डिग्री, पालमपुर में 10.0 डिग्री, सोलन में 10.0 डिग्री, मनाली में 6.2 डिग्री, कांगड़ा में 12.9 डिग्री, मंडी में 12.3 डिग्री, बिलासपुर में 10.0 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 9.8 डिग्री, कुफरी (फागू) में 5.4 डिग्री, कुकुमसेरी में 0.8 डिग्री, सियोबाग में 4.7 डिग्री, बरठीं में 11.6 डिग्री, कसौली में 10.1 डिग्री, पांवटा साहिब में 15.0 डिग्री, सराहन में 3.7 डिग्री, देहरा गोपीपुर में 14.0 डिग्री, ताबो में माइनस 0.4 डिग्री और नेरी में 15.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।

सतत कृषि ही भविष्य की समृद्धि का आधार: नायब सिंह सैनी

जलवायु परिवर्तन, घटते जल स्तर और मृदा स्वास्थ्य को लेकर किसानों को किया जाए जागरूक: मुख्यमंत्री

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित खरीफ कृषि मेला-2026 का शुभारंभ करते हुए किसानों, वैज्ञानिकों और नवाचार को एक मंच पर लाने की पहल को सराहा। उन्होंने कहा कि हिसार की मिट्टी मेहनत, पशुधन समृद्धि और वीर सैनिकों की कुर्बानियों की गवाही देती है। राखीगढ़ी हमारी प्राचीन सभ्यता का गौरव है, जबकि अग्रोहा की धरती महाराजा अग्रसेन के सामाजिक समरसता और व्यापारिक वैभव की कहानी कहती है। कृषि मेले में पहुंचने पर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने शहीदी दिवस के अवसर पर अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की प्रतिमाओं पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा विभाग, कपास अनुभाग, तिलहन विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा किसानों को जानकारी देने के लिए प्रकाशित की गई पुस्तकों का भी विमोचन किया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री बीआर कांबोज ने कृषि मेले में पहुंचने पर मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह के रूप में समृद्ध किसानी का प्रतीक हल भी भेंट किया।

उन्होंने कहा कि आज नवरात्रि के पावन अवसर पर मां स्कंदमाता की आराधना और शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीदी दिवस का संयोग हमें त्याग, तपस्या और समर्पण का संदेश देता है। इसी भावना के साथ कृषि मेले का आयोजन किया गया है, जो ₹सतत कृषि-समृद्धि की राह₹ विषय पर आधारित है।

उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यह मेला किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों की दूरदृष्टि का प्रतीक है। विश्वविद्यालय ने उन्नत बीज, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और जलवायु-स्मार्ट कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भिवानी जिले के गोकुलपुरा में 64 एकड़ में 11.67 करोड़ रुपये की लागत से बने पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र मोटे अनाजों की रोग व कीट प्रतिरोधी किस्मों

के विकास, मिलेट्स आटे की सेल्फ लाइफ बढाने के साथ-साथ उत्पादकों के लिए बाजार संपर्क स्थापित करेगा और उन्नत किस्मों के विकास और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य करेगा। यह केंद्र मिलेट्स उत्पादों के प्रसंस्करण तथा वैल्यू एडिशन की आधुनिक तकनीकें भी विकसित करेगा।

उन्होंने कृषि मेले में 42 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया, जिनमें 21 महिला किसान भी शामिल रहीं। मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश की प्रगति का प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज देश के खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बन चुका है। यह किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों के शोध और सरकार की नीतियों का परिणाम है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत-2047 के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि किसान इस लक्ष्य के आधार स्तंभ हैं। डबल इंजन सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए खेती को लाभकारी उद्यम में बदलने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों जैसे गिरता जल स्तर, मृदा उर्वरता में कमी और जलवायु परिवर्तन का जिक्र करते हुए आधुनिक और सतत खेती अपनाने पर जोर दिया। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, प्राकृतिक और जैविक खेती, तथा आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को समय की आवश्यकता बताया।

मुख्यमंत्री ने फसल विविधीकरण और मेरा पानी-मेरी विरासत योजना का उल्लेख किया, जिसके तहत किसानों को वैकल्पिक फसलें अपनाने पर 8 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 2.20 लाख एकड़ क्षेत्र में इस योजना के तहत 157 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है और जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को तालाब बनाने के लिए भी 85 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने धान, गेहूं के पारंपरिक फसल चक्र से बाहर निकलने के लिए किसानों का आह्वान किया, साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दलहन फसलों के लिए 16 करोड़ 66 लाख रुपये तथा तिलहन फसलों के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि₹ योजना के तहत 20 लाख किसानों को 7,562 करोड़ रुपये और फसल बीमा के तहत 16,160 करोड़ रुपये के क्लेम की राशि भी दी गई है। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत 35 हजार से अधिक किसानों को 157 करोड़ रुपये की राशि भावांतर भरपाई के रूप में दी गई है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने खेती में कीटनाशकों व अत्यधिक खाद के प्रयोग तथा अंधाधुंध पानी के दोहन पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि हमने समय रहते वैकल्पिक उपाय नहीं किए तो हमारी जमीने बंजर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हमें कई प्रकार की दाले और खाद बाहर से आयात करना पड़ता है। हमें खेती के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। इसके लिए गेहूं, धान की खेती के अलावा दालें व अन्य फसलों पर भी फोकस करना होगा। गोबर गैस प्लांट व सोलर प्लांट की पहल करके हम न केवल खुद बल्कि देश को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

हकृवि के कुलपति प्रोफेसर श्री बीआर कांबोज ने मेले के थीम सतत कृषि-समृद्धि की राह विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बदलते समय और जलवायु परिस्थितियों के बीच सतत खेती किसानों की समृद्धि का मजबूत आधार बनकर उभर रही है। यदि किसान आधुनिक खेती के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करे तो न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी लंबे समय तक बनी रहेगी। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे नई तकनीकों और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए सतत खेती की दिशा में कदम बढ़ाएं ताकि कृषि क्षेत्र में स्थाई विकास और समृद्धि सुनिश्चित हो सके।

नलवा से विधायक श्री रणधीर पनिहार ने मुख्यमंत्री तथा अन्य मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ कमल गुप्ता, विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल, विधायक श्री विनोद भयाणा, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया, लुवास के कुलपति डॉ विनोद कुमार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नेता एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

केयू में शहीदी दिवस के अवसर पर किए श्रद्धासुमन अर्पित

सिटी दर्पण संवाददाता

कुरुक्षेत्र

शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा के मार्गदर्शन में छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. ए.आर. चौधरी व अन्य अधिकारियों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद भगत सिंह व अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर प्रो. ए.आर. चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की स्वतंत्रता शहीदों के अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान का परिणाम है। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, जिसकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इन महान विभूतियों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दें।

इस मौके पर प्रॉक्टर प्रो. अनिल गुप्ता, खेल निदेशक प्रो. डी.एस.राणा, कुटा प्रधान डॉ. जितेन्द्र खटकड़, प्रो. कुसुमलता, उप-निदेशक डॉ. सलोनी दीवान, डॉ. मीनाक्षी सुहाग, डॉ.हरविन्द्र राणा, राजपाल सहित शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थी मौजूद रहे।

सांसद नवीन जिन्दल के मार्गदर्शन में मंदिरों की स्वच्छता के लिए रखे गए समर्पण पात्र

सिटी दर्पण संवाददाता

कुरुक्षेत्र

सांसद नवीन जिन्दल द्वारा धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ते हुए एक सराहनीय पहल की गई है। नवीन जिन्दल फाउंडेशन के माध्यम से जिले के ग्यारह मंदिरों में तीन-तीन समर्पण पात्र उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका उद्देश्य पूजा के बाद निकलने वाली सामग्री को अलग-अलग एकत्रित करना है।

यह सभी समर्पण पात्र हल्का पेहवा के काली मंदिर, सरस्वती मंदिर, धनिरामपुरा स्थित बगला मुखी मंदिर व बाला सुंदरी मंदिर, हल्का थानेसर में मां भद्रकाली मंदिर, काली कमली मंदिर व बाला सुंदरी मंदिर हथीरा, हल्का लाडवा में देवी मंदिर और हल्का शाहाबाद में देवी मंदिर धर्मशाला, सिविल अस्पताल के पास शिव मंदिर धर्मशाला व मार्कंडेश्वर

मंदिर के परिसरों में रखवाए गए हैं।

इन सभी समर्पण पात्रों को तीन श्रेणियों में, धूप एवं अगरबत्ती, पूजा के फूल तथा देवी-देवताओं को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र आदि में विभाजित किया गया है। इस व्यवस्था से मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के साथ-साथ जैविक और अजैविक सामग्री के उचित प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा।

त्योहारों के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है, जिससे बड़ी मात्रा में पूजा सामग्री एकत्रित होती है। यदि इसे सही तरीके से अलग नहीं किया जाए, तो यह पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इस पहल के माध्यम से न केवल मंदिर परिसर स्वच्छ रहेंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

सांसद कार्यालय प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि सांसद नवीन जिन्दल का मानना है कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। धार्मिक स्थलों से यदि हम यह संदेश समाज तक पहुंचाते हैं, तो इसका प्रभाव व्यापक और सकारात्मक होता है। श्रद्धालुओं और मंदिर प्रबंधन समितियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे एक प्रेरणादायक कदम बताया है। इस तरह की व्यवस्था से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वे स्वच्छता के प्रति अधिक जिम्मेदार बनेंगे।

नवीन जिन्दल फाउंडेशन की यह पहल न केवल स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती प्रदान करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

संक्षिप्त-समाचार

पंजाब की आप सरकार का ईमानदारी का नकाब उतर चुका : नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का ईमानदारी का नकाब अब उतर चुका है और वहां की जनता उनकी वायदा खिलाफी व भ्रष्टाचार से त्रस्त है। मुख्यमंत्री सोमवार को हिसार में आयोजित कृषि मेले के शुभारंभ के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंजाब की जनता हरियाणा में विकास के माहौल और कल्याणकारी योजनाओं का उदाहरण दे रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने किसानों, व्यापारियों, महिलाओं और युवाओं के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की नीतियों का लाभ सीधे आमजन तक पहुंच रहा है, जिससे प्रदेश निरंतर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने व्यापारियों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण नीति लागू की है, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी आई है और व्यापारिक माहौल बेहतर हुआ है। श्री सैनी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जनता के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है और इसी का परिणाम है कि हरियाणा आज तेज गति से प्रगति कर रहा है। फसल खरीद प्रक्रिया के दौरान रजिस्ट्रेशन के नए नियमों को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने अधिकारियों को प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री को गोहाना रैली का न्यौता, विकास कार्यों को लेकर सौंपा मांगों का प्रस्ताव

चंडीगढ़। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने आगामी 29 मार्च को गोहाना की नई सब्जी मंडी में आयोजित होने वाली गोहाना विधानसभा धन्यवाद एवं विकास रैली में मुख्यातिथि के रूप में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को औपचारिक निमंत्रण दिया। डॉ. शर्मा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि यह रैली सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से क्षेत्र के विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने गोहाना विधानसभा क्षेत्र के हालिया दौरों के दौरान जनता से प्राप्त मांगों और समस्याओं की विस्तृत सूची भी मुख्यमंत्री को सौंपी। उन्होंने आग्रह किया कि इन मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक घोषणाएं की जाएं, ताकि क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने का आश्वासन देते हुए सकारात्मक रुख दिखाया। मुलाकात के दौरान विभिन्न विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

शहीदों के बलिदान से ही सुरक्षित है देश की आजादी: स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज शहीदी दिवस के अवसर पर देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 23 मार्च का दिन भारतीय इतिहास में अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक है। यह दिन हमें महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अद्वितीय बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि इन वीर सपूतों ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष का जो संदेश दिया, वह आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत हमें यह सिखाती है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। देशहित में किया गया प्रत्येक

त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। उनके साहस, त्याग और समर्पण ने देशवासियों को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया और एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी। आरती सिंह राव ने कहा कि वर्तमान समय में शहीदों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही हम एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शहीदों और उनके परिवारों के सम्मान एवं कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शहीद परिवारों को सहयोग और सम्मान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और उनके सम्मान में कोई कमी न आने दें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शहीदों का बलिदान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है। उनके आदर्श हमें हर परिस्थिति में राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आरती सिंह राव ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा और उनका बलिदान हर भारतीय के दिल में राष्ट्रभक्ति की भावना को सदा जीवित रखेगा।

आपदा मित्रों ने कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थलों के साथ ऐतिहासिक साइट का किया भ्रमण

सिटी दर्पण संवाददाता

कुरुक्षेत्र

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से आपदा मित्रों को कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों के साथ साथ ऐतिहासिक साइट का भ्रमण करवाया गया। इसके साथ ही इन आपदा मित्रों को जिले के उन इलाकों का भी अवलोकन करवाया गया, जो समय समय पर आपदा के केंद्र बने रहे।

जिला राजस्व अधिकारी चेतना चौधरी ने कहा कि राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संख्या-2 में युवा आपदा मित्र योजना के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान युवा आपदा मित्रों ने महाभारत अनुभव केंद्र का भ्रमण किया। यह महाभारत अनुभव केन्द्र आम नागरिकों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हैं। इस अनुभव केंद्र में 5 ब्लॉक बनाए गए हैं।

हर ब्लॉक में महाभारत को आधुनिक तकनीकी से विशेष एलईडी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। हर ब्लॉक में 2 से 3 मिनट के चलचित्र चलाएं जाते है। इन चलचित्रों में द्रौपदी स्वयंवर, श्रीकृष्ण अर्जुन के संवाद, भीष्म पितामह के तीरों की शईयां पर जैसे दृर्शयों को दिखाया गया हैं।

इसके अलावा युवा आपदा मित्रों ने झांसा डैम का भी भ्रमण किया और युवा आपदा मित्र द्वारा सीएसएसएसआर के अंतर्गत मलबे में फंसे लोगों की खोज एवं सुरक्षित बचाव के तरीकों की जानकारी देने के साथ-साथ मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस, मेडिकल फर्स्ट रिस्पांस से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकों पर जानकारी साझा की। इसके अलावा इन युवा आपदा मित्रों द्वारा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजी व न्यूक्लियर जैसी आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक सावधानियां एवं बचाव उपायों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई है।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी साइंस इंडस्ट्री में कॉमर्शियल गैस की निरंतर उपलब्धता के लिए उच्च अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए

सिटी दर्पणस ंवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज अम्बाला छावनी की साइंस इंडस्ट्री में मध्य-पूर्व युद्ध से उत्पन्न हुए कामर्शियल गैस संकट को लेकर प्रदेश के उच्च अधिकारियों से बातचीत करते हुए इसके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साइंस उद्यमियों के लिए कॉमर्शियल गैस की निरंतर उपलब्धता होनी चाहिए ताकि इनके कामकाज प्रभावित न हों।

श्री विज के अम्बाला छावनी स्थित आवास पर आज अम्बाला छावनी साइंस इंडस्ट्री से ह्रद अम्बाला साईंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशनह्व और ह्रसाईंटिफिक अप्रेंट्स मैन्यूफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टसह्व के पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए गैस उपलब्धता के लिए गुहार लगाई।

एसोसिएशन पदाधिकारियों की मांग को त्वरित कार्रवाई करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त एवं सचिव जे. गणेशन से बात की और साइंस इंडस्ट्री में निरंतर कॉमर्शियल गैस उपलब्धता जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि अम्बाला छावनी में हजारों घरों की रोजी-रोटी साइंस इंडस्ट्री है और गैस उपलब्ध नहीं होने पर काम प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइंस इंडस्ट्री में गैस आपूर्ति का अलग से शेड्यूल तय कर यहां निरंतर गैस उपलब्ध कराई जाए। ऊर्जा मंत्री अनिल विज डीसी अम्बाला अजय तोमर से भी इस मामले में कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश दिए ताकि साइंस उद्यमियों को गैस किल्लत से जुझना न पड़े।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई पर एसोसिएशन सदस्यों व साइंस उद्यमियों ने उनका धन्यवाद जताया। साइंस उद्यमी व एसोसिएशन अध्यक्ष जतिंद्र सहगल के अलावा संजय गुप्ता, सौरभ नागपाल, नवनीत मित्तल, उमाकांत, मुकेश चोपड़ा, रजत जैन, गुरकिरपाल सिंह आदि ने बताया कि कॉमर्शियल गैस संकट की वजह से साइंस ग्लासवेयर इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ रहा है।

वहीं, ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मध्य-पूर्व में युद्ध से उत्पन्न हुए तेल व गैस संकट पर कहा कि अब जो समस्या उत्पन्न हुई है वह हिंदुस्तान की वजह से नहीं बल्कि दूसरी शक्तियों की वजह से उत्पन्न हुई है जो आपस में लड़ रही है।

उन्होंने कहा कि इस वजह से तेल और गैस लाने का मार्ग अवरुद्ध हुए है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति के बल पर हम अपने फंसे हुए जहाजों को निकलवा सके है जिनके जरिए तेल व गैस आपूर्ति हो रही है। भारत के जो शेष 22 जहाज फंसे है जिनमें लगभग 166 नाविक है उन्हें निकलवाने के लिए भी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वे जनता से यह कहना चाहते हैं कि वह घबराएं नहीं क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न आए।

वहीं गैस संकट को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि हुड्डा ने तो हमेशा घी में आग डालने का काम किया है और उनका इतिहास उठाकर देखा जा सकता है, इसलिए वह अपने काम में लगे हुए हैं।

रुपये की गिरावट से उजागर हुई आर्थिक कुप्रबंधन की सच्चाई: कुमारी सैलजा

सिटी दर्पणस ंवाददाता

चंडीगढ़

सिरसा की सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी सैलजा ने देश की वर्तमान आर्थिक और कूटनीतिक परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज भारत कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। रुपये की गिरती स्थिति केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह केंद्र सरकार की नीतियों, निर्णय क्षमता और वैश्विक साख पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार बार-बार आर्थिक मजबूती के दावे करती रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि महंगाई, बेरोजगारी और मुद्रा का अवमूल्यन आम जनता की कमर तोड़ रहा है। रुपये की कमजोरी यह दशार्ती है कि सरकार आर्थिक प्रबंधन में संतुलन और दूरदर्शिता बनाए रखने में असफल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की

आर्थिक नीति हमेशा संतुलन, समावेशी विकास और जनहित पर आधारित रही है। कांग्रेस मानती है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए छोटे व्यापारियों, किसानों और मध्यम वर्ग को सशक्त करना आवश्यक है। केवल बड़े उद्योगों पर केंद्रित नीतियां देश की आर्थिक नींव को कमजोर करती हैं।

विदेश नीति के संदर्भ में कुमारी सैलजा ने कहा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न एलपीजी संकट जैसे मुद्दों ने भारत की कूटनीतिक स्थिति को चुनौती दी है। पहले भारत की पहचान एक मजबूत और संतुलित वैश्विक नेतृत्व की थी, लेकिन वर्तमान में कई देशों के साथ संबंधों में स्पष्टता और स्थिरता की कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विदेश नीति हमेशा संवाद, संतुलन और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पर आधारित रही है। भारत को वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद और स्थिर साझेदार के रूप में स्थापित करना आवश्यक है, न कि केवल आक्रामक बयानबाजी तक सीमित रहना चाहिए। कुमारी सैलजा ने अंत में कहा कि देश को ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो आर्थिक स्थिरता, सामाजिक न्याय और मजबूत अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुनिश्चित करें। कांग्रेस पार्टी हमेशा रचनात्मक सुझावों और जनहित के मुद्दों पर सरकार का मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह देशहित में ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए, ताकि भारत की आर्थिक स्थिति और वैश्विक साख को पुनः मजबूत किया जा सके।

संपादकीय

8,931 दिन का रिकॉर्ड : कैसे नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले प्रधानमंत्री?

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तब स्थापित हुआ, जब नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए। 8,931 दिनों का यह कार्यकाल केवल समय की गणना नहीं है, बल्कि यह उस राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है, जिसने भारत के शासन तंत्र को नई दिशा दी है। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उदय एक साधारण पृष्ठभूमि से शुरू होकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचने की कहानी है। 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, तब देश आर्थिक सुस्ती, भ्रष्टाचार के आरोपों और नीति-निर्माण में ठहराव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा था। उन्होंने खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया, जो कठिन और बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते। यही उनकी नेतृत्व शैली की सबसे बड़ी पहचान बन गई। मोदी सरकार के कार्यकाल में कई बड़े और प्रभावशाली फैसले लिए गए। 2016 की नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया, जिसका उद्देश्य काले धन और नकली मुद्रा पर रोक लगाना था। इसके बाद 2017 में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, जिसने देश को एकीकृत कर प्रणाली की ओर अग्रसर किया। 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला भी ऐतिहासिक रहा, जिसने राज्य की विशेष स्थिति को समाप्त कर उसे पूर्ण रूप से भारतीय संघ में शामिल कर दिया। इन फैसलों के समर्थक इन्हें राष्ट्रहित में उठाए गए साहसिक कदम मानते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि इनके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को लेकर पर्याप्त तैयारी नहीं की गई। विशेष रूप से नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर के शुरूआती चरण में छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार की एक और महत्वपूर्ण पहचान उसकी जनकल्याणकारी योजनाएं रही हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया।आयुष्मान भारत योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास किया, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया गया। इन योजनाओं ने समाज के निचले तबकों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाई है। डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आधार और मोबाइल तकनीक के माध्यम से सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने की व्यवस्था ने भ्रष्टाचार को कम करने में मदद की है। हालांकि, इन उपलब्धियों के साथ कई चुनौतियां भी बनी रहीं। बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट जैसे मुद्दे लगातार सरकार के सामने रहे हैं। विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की नीतियों को लेकर भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आईं। शुरूआती लॉकडाउन को जहां सख्त और आवश्यक कदम माना गया, वहीं प्रवासी मजदूरों की समस्याओं ने प्रशासनिक खामियों को उजागर किया। विदेश नीति के क्षेत्र में मोदी सरकार ने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को नई दिशा दी गई। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रियता बढ़ी और देश ने खुद को एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व की भूमिका निभाई, जिससे उसकी कूटनीतिक छवि और मजबूत हुई। मोदी के लंबे कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी राजनीतिक रणनीति और संचार कौशल भी रहा है। उन्होंने चुनावी राजनीति में एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट संदेश और डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग शामिल है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने सीधे जनता से संवाद स्थापित किया, जिससे उनकी लोकप्रियता में लगातार वृद्धि हुई। हालांकि, इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, मीडिया की भूमिका और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी बहस तेज हुई है। विपक्षी दलों और कई विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह प्रभावी और तेज निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। 8,931 दिनों का यह कार्यकाल भारतीय राजनीति में स्थिरता और निरंतरता का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि देश में मजबूत नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। साथ ही, यह भी स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र में लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए लगातार जनसमर्थन और प्रभावी शासन आवश्यक है। आने वाले समय में मोदी सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी। आर्थिक विकास को गति देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, सामाजिक समरसता बनाए रखना और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को और मजबूत करना–ये सभी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सरकार की सफलता का आकलन किया जाएगा। अंततः, नरेंद्र मोदी का 8,931 दिनों का यह कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। यह न केवल एक नेता के लंबे शासन की कहानी है, बल्कि उस परिवर्तन का भी प्रतीक है, जो भारत ने पिछले एक दशक में अनुभव किया है। यह दौर भविष्य में राजनीतिक विश्लेषण और अध्ययन का एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा।

नक्सल मुक्त भारत की संकल्पना होने लगी साकार

विक्रम उपाध्याय (हि.स)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारत को नक्सल-मुक्त बनाने की समय सीमा 31 मार्च 2026 तय की थी। इसलिए यह जानना जरूरी है कि क्या सचमुच सरकार ने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है? क्या अब नक्सल हिंसा में किसी नागरिक को बेवजह जान नहीं गंवानी पड़ेगी? यह कहने में अब किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत सचमुच वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में ऐतिहासिक सफलता हासिल कर चुका है। आंकड़े इसके गवाह हैं। जहां 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, वह 2025 के अंत तक घटकर सिर्फ तीन ही रह गई और उनमें भी कोई बड़ा नक्सली नेता जीवित या सक्रिय नहीं बचा। यानी नक्सल हिंसा से मुक्ति की संकल्पना सच होने लगी है।

एक समय था जब छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार समेत आधा दर्जन राज्यों में रेड कॉरिडोर स्थापित था। जहां से नक्सली बड़े बड़े हिंसक अभियान चलाते थे। लेकिन 2014 के बाद शुरू हुए नक्सल उन्मूलन अभियान ने तस्वीर बदल कर रख दी है। एक दशक से भी कम समय में नक्सल प्रभावित इलाकों में 600 से ज्यादा नए और आधुनिक पुलिस थाने बनाए गए हैं और हर जगह आसानी से सुरक्षा बलों को पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तैयार किए गए हैं। लेकिन जो नक्सली हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के लिए तैयार हुए, उन्हें आत्मसमर्पण के लिए सम्मानजनक जीवन के विकल्प भी दिए गए। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए विकास और सुरक्षा की योजनाएं ईमानदारी से लागू की गई हैं और और जिन अतिवादियों ने फिर भी हिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा, उनके सफाए के लिए सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) को पूर्ण अधिकार दे दिया गया।

सुरक्षा बलों को जब ऑपरेशन वाले क्षेत्र के नक्शे, हेलीकॉप्टर और अन्य सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए तो कुछ समय बाद ही नक्सलियों की बादशाहत खत्म होने लगी। घात लगाकर हमलों और छापों के जरिए निर्दोष लोगों को मारने वाले नक्सली खुद को बचाने में ही परेशान होने लगे। सबसे बड़ी बात यह रही कि नक्सल विरोधी अभियानों में नियमित सैनिकों को शामिल नहीं किया गया।

इतिहास की बात करें तो 60 के दशक में नक्सल आंदोलन का जन्म बंगाल में आदिवासियों के खिलाफ पुलिस और जमींदारों के बीच संघर्ष के कारण हुआ, लेकिन जब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता माओ जेडोंग इस आंदोलन के वैचारिक केंद्र बन गए तो इसका स्वरूप भारतीय सरकारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में बदल गया। नक्सलियों के लिए हथियार पश्चिम बंगाल में ही बनाए जाने लगे। कोलकाता का प्रेसीडेंसी कॉलेज नक्सलवाद का गढ़ बन गया। फिर सान्याल और मजूमदार के गुट वाली वामपंथी पार्टी ने हिंसक क्रांति का मार्ग चुना और भारतीय राज्य की नींव को ही उखाड़ फेंकने का विचार फैलाया। बाद में कुछ राजनीतिक पार्टियां भी सत्ता के लिए नक्सलियों का इस्तेमाल करने लगीं।

वर्ष 2004 में जब पीपुल्स वार ग्रुप और माओइस्ट कॉम्युनिस्ट सेंटर का विलय हुआ तो हिंसा उन इलाकों में भी फैल गई जहां पहले शांति थी। भारतीय सत्ता के खिलाफ लगातार हिंसक संघर्ष देखा गया। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा नक्सल गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। वर्ष 2010 में 76 सी आरपीएफ जवानों का कत्ल हुआ तो 2012 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कलेक्टर का अपहरण हो गया और फिर 2013 में सलवा जुडूम शुरू करने वाले महेंद्र कर्मा समेत कई बड़े नेताओं और सुरक्षा कर्मियों की हत्या नक्सलियों ने कर दी।

लेकिन 2014 में अपनी सरकार बनाने से पहले ही नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की धरती से ही यह ऐलान कर दिया कि धरती को लाल करने का नारा देने वाले या तो धरती को हरा-भरा करने के उद्देश्य के साथ मुख्यधारा में लौट आएं या फिर आरपार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। जब गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने जिम्मेदारी संभाली तो तय हो गया कि अब भारत वामपंथी उग्रवाद को सहन नहीं करेगा और इसे पूरी तरह से खत्म करने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए 31 मार्च, 2026 की समय सीमा तय की गई और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ स्पष्ट रणनीति बनाई गई। माओवादी हिंसा के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' की दृढ़ नीति बनाकर इसे व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का हिस्सा बना दिया गया।

गृह मंत्रालय के नेतृत्व में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित अभियान शुरू किए गए और एक मजबूत खुफिया तंत्र विकसित किया गया। शीर्ष माओवादी नेतृत्व के मूवमेंट के बारे में रियल टाइम की सूचनाएं प्राप्त कर उनको खत्म किया जाने लगा। जो आत्मसमर्पण करना चाहते थे उन्हें पुनर्वास का विकल्प दिया गया। ऑपरेशन इतना सटीक चलाया गया कि 2025 तक, नक्सलवाद के नेतृत्व को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में फिर दावा किया कि मार्च के अंत तक भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा।

सरकार के दावे को नकारा नहीं जा सकता। नक्सली उग्रवाद पर लगाम के जो आकड़े उपलब्ध हैं, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केंद्र और प्रभावित राज्यों ने मिलकर छह दशक से भी पुराने इस हिंसक आंदोलन को पहली बार पूरी तरह से कुचलने में कामयाब हुए हैं। 2014-24 के बीच हिंसक घटनाओं में भारी कमी आई। नक्सलियों के हाथों सुरक्षा बलों के मारे जाने की घटनाओं में लगभग 73 प्रतिशत और नागरिकों की मौतों में लगभग 70 प्रतिशत की सीधी कमी देखी गई। अब केवल छत्तीसगढ़ के तीन जिलों के कुछ हिस्सों में ही नक्सलियों की उपस्थिति सीमित रह गई है और उन्हें भी नक्सल मुक्त करने का अभियान जारी है।

कई राज्यों ने तो आधिकारिक तौर पर खुद को नक्सल-मुक्त घोषित कर दिया है। बिहार और मध्य प्रदेश इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। माओवादी नेता देवूजी के आत्मसमर्पण के बाद तेलंगाना भी अब नक्सल मुक्त हो चुका है। नक्सल कैडर अब किस तरह से हताश हो चुके हैं, वे इन आकड़ों से पता चलता है कि अकेले 2024-25 में ही लगभग 2,900 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और 1,900 से अधिक की गिरफ्तारियां हुईं। यही नहीं 600 से अधिक माओवादियों को मुठभेड़ में खत्म भी किया गया। पांच, दस नहीं, बल्कि 28 शीर्ष माओवादी नेताओं को भी खत्म कर दिया गया। जिनमें माओवादी वाम महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू, केंद्रीय समिति के सदस्य पतिराम मांझी और गणेश उइके जैसे बड़े नक्सली नेता शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने एक तरफ सख्त सुरक्षा अभियान और कोइ ढिलाई नहीं की नीति अपनाई वहीं, विकास के वृहद कार्यक्रम चलाए और सबके पसंद के पुनर्वास प्रोग्राम भी शुरू किये। इस रणनीति के कारण ही स्थानीय लोगों का माओवादी नेताओं से मोहभंग हुआ और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में सफलता हासिल हुई। मोदी सरकर ने एक तरफ सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियान को नई धार दी तो वहीं उग्रवाद प्रभावित लोगों की सामाजिक व आर्थिक जरूरतों का भी पूरा ख्याल किया। इसके कारण ही ऑपरेशन आक्टोपस, डबल बुल, चक्रबंध और ब्लैक फॉरेस्ट को कामयाबी मिली। स्थानीय लोगों ने भी सरकार के खुफिया-आधारित अभियानों का समर्थन किया।

मोदी सरकार ने नक्सल विरोधी अभियान के लिए केवल सुरक्षा बल के प्रयोग को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि लगभग 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण जंगल क्षेत्रों में कर डाला, 6,500 से अधिक मोबाइल टावरों की स्थापना की और 1,800 से अधिक शाखाओं के साथ बैंकिंग के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया, ताकि योजनाओं के पैसे लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नक्सल उन्मूलन की यह सफलता बताती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और स्पष्ट नीति के साथ कोई काम किया जाए तो उसके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

आज का राशिफल

मेष: पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। शुभ कार्यों की प्रवृत्ति बनेगी और शुभ समाचार भी मिलेंगे। किसी से कहा सुनी न हो यही ध्यान रहें। अपना कार्य दूसरों के सहयोग से बना लेंगे। लाभकारी गतिविधियों में सक्रियता रहेगी। कुछ एकाग्रता की प्रवृत्ति बनेगी। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: अपने संघर्ष में स्वयं को अकेला महसूस करेंगे। विशेष परिश्रम से अभिष्ट कार्य सिद्ध होंगे। व्यर्थ प्रपंच में समय नहीं गंवाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। बनते हुए कार्यों में बाधा आएगी। विरोधियों के सक्रिय होने की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। रोजगार में तरक्की मिलेगी। जमीन जायदाद का लाभ भी हो सकता है। आवास, मकान तथा वाहन की सुविधाएं मिलेंगी। कर्ज तथा रोगों से मुक्ति भी संभव है। शत्रुओं की पराजय होगी। कुछ आर्थिक समस्याएं भी दूर होंगी होगी। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: उच्चमनोबल रखकर कार्य करें, सफल होंगे। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। आय-व्यय की स्थिति समान रहेगी। शैक्षणिक कार्य आसानी से पूरे होते रहेंगे। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: यात्रा का दूरगामी परिणाम मिल जाएगा। कामकाज में आ रही बाधा को दूर कर लेंगे। सुविधा और समन्वय बना रहने से कामकाज में प्रगति बनेगी। लाभदायक कार्यों की चेष्टाएं प्रबल होंगी। बुद्धितत्व की सक्रियता से अल्प लाभ का हर्ष होगा। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: घर-परिवार में प्रसन्नता व सहयोग का वातावरण बनेगा। रुका हुआ लाभ आज प्राप्त हो सकता है। मानसिक एवं शारीरिक शिथिलता पैदा होगी। व्याधिक्य का अवसर आ सकता है। कामकाज की अधिकता रहेगी। लाभ भी होगा और पुराने मित्रों का समागम भी। *(सिटी दर्पण)*

तुला: संतान की प्रगति से संतोष होगा। व्यर्थ की भाग-दौड़ में समय व्यतीत होगा। श्रम अधिक करना पड़ सकता हैं। वरिष्ठजनों से मतभेद उभर सकते हैं। समय नकारात्मक परिणाम देने वाला बन रहा है। कलह विवाद का डर बना रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: अपना कार्य दूसरों के सहयोग से बना लेगें। प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले सामाजिक कार्य संपन्न होंगे। आमोद-प्रमोद का दिन होगा और व्यावसायिक प्रगति भी होगी। ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि होगी और सज्जनों का साथ भी रहेगा। कुछ कार्य भी सिद्ध होंगे। *(सिटी दर्पण)*

धनु: कार्यक्षेत्र में विवाद बढ़ेंगे। परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होगी। किसी का अभद्र व्यवहार खिन्नता व तनाव बढ़ायेगा। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने में रुकावट का एहसास होगा। मनोरथ सिद्धि का योग है। *(सिटी दर्पण)*

मकर: आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। कोई प्रिय वस्तु अथवा नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। मान-सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक आस्थाएं फलीभूत होंगी। सुख-आनंद कारक समय है। लाभदायक कार्यों की चेष्टाएं प्रबल होंगी। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: बुद्धितत्व की सक्रियता से अल्प लाभ का हर्ष होगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनाने के लिए भाग-दौड़ रहेगी। सुखद समय की अनुभूतियां प्रबल होंगी। मनोविनोद बढ़ेंगे। व्याधिक्य का अवसर आ सकता है। शुभ कार्यों का लाभदायक परिणाम होगा। *(सिटी दर्पण)*

मीन: व्यर्थ की भाग-दौड़ से यदि बचा ही जाए तो अच्छा है। जरा-सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। मानसिक व्यथा व संतान के कारण परेशानी होगी। आवेश में आना आपके हित में नहीं होगा, इसलिए व्यवहार व वाणी पर नियंत्रण रखें। पुरानी गलती का पश्चाताप होगा। *(सिटी दर्पण)*

बदल गया है दिल्ली का राजनीतिक भूगोल

बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्यों- त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार इत्यादि राज्यों की तरह दिल्ली का भी राजनीतिक समीकरण पिछले कुछ सालों में बेहिसाब बदल गया है। इसी का परिणाम है कि चुनाव जीतने के हर तरकीब अपनाने के बावजूद 27 साल बाद पिछले साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में करीब तीन फीसदी के अंतर से भाजपा चुनाव जीत पाई। सीटों में काफी अंतर रहा। 70 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा को 48 और दस साल से प्रचंड बहुमत से सरकार में काबिज आम आदमी पार्टी(को 22 सीटें मिली। यह साबित हो चुका है कि बिहार से सीमांचल में मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा हो गई कि भाजपा की जीत तभी हो पाई जब एआईएआईएम जैसी मुस्लिम पार्टी ने पांच सीटें जीतीं और कई सीटों पर अच्छी संख्या में वोट हासिल पर पाई। यही स्थिति असम में भी पिछले चुनाव में हुई। दिल्ली में 2011 की जनगणना के हिसाब से मुस्लिम आबादी 15 फीसदी हैं। उससे पहले उनका औसत 12 फीसदी था। अब जब भी जनगणना होगी इसमें और बढ़ोतरी होना तय सा है।

आजादी के बाद से दिल्ली की आबादी का अनुपात या यूं कहें तो जातीय समीकरण बदलता रहा है। आजादी के बाद बड़ी संख्या में पाकिस्तान से हिंदू और सिख दिल्ली आए। उनमें कांग्रेस का भी समर्थन करने वालों की संख्या थी लेकिन ज्यादातर जनसंघ (आज की भाजपा) के समर्थक थे। यह मान लिया गया था कि पाकिस्तान से आए विस्थापित, सरकारी कर्मचारी, सवर्ण हिंदू और वैश्य इत्यादि जनसंघ के और दिल्ली देहात के गांव के रहने वाले, पुरानी दिल्ली के मुसलमान और गरीब बस्तियों में रहने वाले कांग्रेस के समर्थक होते हैं। दिल्ली में शुरू से ही रोजगार, कारोबार और पढ़ाई करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते रहा हैं। अपना समर्थन बढ़ाने के लिए कांग्रेस की केन्द्र सरकार ने इमरजेंसी में अनेक पुनर्वास कालोनियां बसाईं और उस इलाके से कांग्रेस लगातार जीतती रही। 1982 के एशियाड खेलों के आयोजन में बड़े पैमाने पर दिल्ली में निर्माण हुए। उसके लिए बाहर से मजदूर आए और फिर बाहर से आने वालों का सिलसिला बढ़ता गया। माना गया कि दिल्ली की स्वाभाविक आबादी में होने वाली बढ़ोतरी के साथ-साथ हर साल करीब पांच साल अतिरिक्त आबादी दिल्ली में जुड़ जाती है। इसी की आड़ में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी दिल्ली में भी घुसपैठ करके वोट और नोट की राजनीति में दिल्ली के नागरिक बनते जा रहे हैं। उन्होंने कई नए इलाकों को मुस्लिम बहुल बना दिया है।

मनोज कुमार मिश्र (हि.स)

यह आबादी पहले आंख मूंदकर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट करती रही। मुस्लिम आबादी के चक्कर में भाजपा के नेता झुग्गी और अनधिकृत कालोनियों में रहने वालों का विरोध करके एक बड़े वर्ग को अपना विरोधी बना लिया। पहले यह वर्ग कांग्रेस के साथ था, आप ने राजनीति ही इन्हीं लोगों को अपने पक्ष में करने से किया। उनका हर तरह से समर्थन करने के साथ-साथ आप ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटी। कांग्रेस के नेता छुप-छुपाकर इनका समर्थन करते थे, आआपा के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल समेत हर नेता इन घुसपैठियों का खुलेयाम समर्थन करते हैं। उल्टे-सीधे प्रयासों से आआपा ने कांग्रेस के समर्थक माने जाने वाले कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यक और पूर्वांचल(पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड आदि के मूल निवासी) के प्रवासियों को अपना स्थाई वोटर बना लिया। 2013 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अल्पसंख्यकों ने गलतफहमी में कांग्रेस के वोट दिया। तब उन्हें लगा कि भाजपा को कांग्रेस हरा रही है। उसके बाद के दोनों विधानसभा चुनावों में इस वर्ग ने आप को वोट किया। आप रिकार्ड सीटों से सत्ता में रही।

आजादी के समय मुस्लिम आबादी पुरानी दिल्ली तक सिमटी हुई थी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया बनने के काफी सालों बाद जामिया के आस-पास के नए और पुराने मोहल्ले मुस्लिम आबादी वाले हुए। बल्कि 2019 में नागरिक संशोधन एक्ट (सीएए) लागू किए जाने के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन उसी इलाके के शाहीन बाग में 15 दिसंबर, 2019 से 8 फरवरी, 2020 तक चला। उस कानून में पड़ोसी देशों में रहने वाले हिंदू, सिख, बौध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। कहा जा रहा था कि विरोध सीएए लागू होने से ज्यादा यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) लागू किए जाने से रोकने के लिए किया गया था। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहली राज्य बन गया है। इन दोनों को देश भर में कब लागू किया जाएगा कहा नहीं जा सकता है।

दिल्ली में पहले विधानसभा की चार सीटें ऐसी थीं जहां मुस्लिम आबादी 20 फीसदी से ज्यादा थी। पहले मुस्लिम आबादी का औसत दस फीसदी से नीचे थी। 2001 में 12 फीसदी हुआ और 2011 में यह 12 से बढ़कर अब 15 फीसद से ज्यादा हो गई है। नई जनगणना में यह और बढ़ने की संभावना है। 70 में से 17 सीटें ऐसा हैं जहां मुस्लिम मतदाता 20 फीसद से ज्यादा हैं। इनमें सीलमपुर, मटिया महल, बल्लीमरान, ओखला, मुस्तफाबाद, किराड़ी, चांदनी चौक, गांधीनगर, करावल नगर, विकास पुरी, ग्रेटर कैलाश, कस्तूरबा नगर, बाबरपुर, मोतीनगर, मालवीय नगर, सीमापुरी और छत्तरपुर शामिल हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बदले अनुपात के चलते ही अनुसूचित जाति का औसत 18 से घटकर 17 हो गया। इसके चलते अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 13 से घट कर 12 हो गई। दिल्ली के 70 में से 42 सीटों पर पूरबियों (पूवार्चंल के प्रवासी) का वोट 20 फीसद से ज्यादा है। इसके चलते पिछले कई चुनावों से पूरबिए नेताओं को दिल्ली की राजनीति में महत्व मिलने लगा। सबसे पहले बिहार मूल के महाबल मिश्र को कांग्रेस ने पहले विधायक और सांसद का टिकट दिया। उसके बाद भाजपा ने भोजपुरी के लोकप्रिय कलाकार मनोज तिवारी को सांसद और प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए पहले बिहार मूल के नेता कीर्ति आजाद को प्रदेश अध्यक्ष बनाना तय किया गया।

वे पहले भाजपा के दिल्ली से विधायक और बिहार से सांसद थे। अचानक कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता सुभाष चोपड़ा को अध्यक्ष और आजाद को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। गुटबाजी में आजाद अलग-थलग हो गए, उन्हें दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में नियमित बैठने के लिए कमरा तक नहीं दिया गया। बाद में चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर लोकसभा के सदस्य बन गए। 2020 के विधानसभा चुनाव के कुछ समय बाद कांग्रेस के पूर्वांचल के सबसे लोकप्रिय चेहरा रहे पूर्व सांसद महाबल मिश्र भी कांग्रेस छोड़कर आआपा में शामिल हो गए। इस बार आआपा ने उन्हें पश्चिमी दिल्ली से लोक सभा उम्मीदवार बनाया। उनके पुत्र विनय मिश्र पहले से ही आआपा में शामिल होकर विधायक बने। इस बार वे भी पराजित हुए।

पुरबिए वोट तो प्रयास करने से कम-ज्यादा भाजपा को मिलते रहे हैं और भविष्य में भी मिलेंगे।

उत्तराखंड के प्रवासियों का लगातार समर्थन भाजपा को मिलता रहा है। उसमें कम विभाजन हुआ है। इसके अलावा भाजपा को परंपरागत वोट भी मिलते रहे हैं, अब समीकरण बदल गए हैं और लगातार बदलते जाएंगे। दिल्ली विधानसभा पिछले कई चुनावों में भाजपा केवल इसलिए हार रही थी कि उसके खिलाफ वोट करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भाजपा के लिए आसान विकल्प तो यह है कि वह असम और बिहार जैसे मजबूत तीसरा विकल्प बनाए जैसा अगले महीने होने वाले चुनाव में भाजपा असम का फामूर्ला पश्चिम बंगाल में आजमाने की कोशिश कर रही है। यह विकल्प स्थाई नहीं हो सकता है। जिस तरह से नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली केन्द्र सरकार के गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च, 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने के अपने वादे को पूरा करके दिखाया, उसी तरह सरकार को देश को तय समय सीमा में विदेशी घुसपैठ से मुक्त करने का संकल्प लेना होगा।

देश की राजधानी दिल्ली इस बार तो हर संभव प्रयास करके भाजपा जीत ली है लेकिन आगे जीतना संभव नहीं होगा। तीन फीसदी का अंतर स्थाई नहीं माना जा सकता है। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि कई बार से लगातार दिल्ली की लोकसभा की सभी सीटें भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम पर जीतती रही है। अगर ऐसा होता तो पहले भी जीत होती। इस विधानसभा चुनाव में भी मिली जीत में एक बड़ा योगदान प्रधानमंत्री का नाम होगा, वोट समीकरण ठीक किए बिना स्थाई जीत संभव नहीं हैं। केन्द्र सरकार को अनुच्छेद 370 हटाने, तीन तलाक खत्म करने और सीएए जैसे कड़े फैसले लेने होंगे।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

घोषणाओं का पहाड़, हकीकत की खाई: हिमाचल बजट 2026-27 की असल कहानी

अतुल ठाकुर

हिमाचल प्रदेश का बजट 2026-27 जब विधानसभा में पेश हुआ, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को उम्मीद थी कि इस बार राज्य की आर्थिक चुनौतियों, बढ़ती बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर कोई ठोस दिशा दिखाई देगी। पहाड़ों में रहने वाले आम लोगों की जरूरतें बहुत बड़ी नहीं होतीं—उन्हें चाहिए स्थिर आय, बेहतर सड़कें, भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं और अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य। लेकिन जब इस बजट को ध्यान से पढ़ा और समझा गया, तो लगा कि यह उम्मीदों से ज्यादा समझौतों का दस्तावेज बनकर सामने आया है।

सरकार ने अपने बजट में किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही है। यह निश्चित रूप से सराहनीय दिशा है, क्योंकि हिमाचल की आत्मा उसके गांवों और किसानों में बसती है। लेकिन समस्या यह है कि इन बातों में स्पष्टता और ठोस कार्ययोजना की कमी साफ दिखाई देती है। सबसे पहले बात राज्य की आर्थिक स्थिति की करें, तो यह किसी से छिपी नहीं है कि हिमाचल इस समय वित्तीय दबाव से गुजर रहा है। राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा है और इस बजट में भी यह हजारों करोड़ रुपये के स्तर पर है। इसके साथ ही केंद्र से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान बंद हो चुका है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या कर रही है? बजट में इसका कोई स्पष्ट उत्तर नजर नहीं आता। न तो आय बढ़ाने के नए स्त्रोतों की ठोस योजना है और न ही निवेश आकर्षित करने की कोई आक्रामक रणनीति।

हिमाचल जैसे राज्य के लिए पर्यटन, जलविद्युत और छोटे उद्योग सबसे बड़े अवसर हैं। लेकिन इस बजट में इन क्षेत्रों को लेकर कोई बड़ा विजन या नई पहल दिखाई नहीं देती। पर्यटन, जो राज्य की पहचान और आय का प्रमुख साधन है, उसे वैश्विक स्तर पर ले जाने की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं दिखती। इसी तरह, उद्योगों को बढ़ावा देने या निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी कोई ठोस रोडमैप सामने नहीं आया है। सरकार द्वारा मंत्रियों, विधायकों और उच्च अधिकारियों के वेतन को छह महीने तक स्थगित करने का फैसला भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे कुछ लोग सादगी और जिम्मेदारी का प्रतीक मान सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर यह राज्य की आर्थिक मजबूरी को भी उजागर करता है। यह कदम यह संकेत देता है कि सरकार फिलहाल संकट को टालने की कोशिश कर रही है, न कि उसे स्थायी रूप से हल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं जरूर की गई हैं—जैसे टरढ में वृद्धि, सब्सिडी और किसान आयोग का गठन। लेकिन हिमाचल का किसान यह भली-भांति जानता है कि असली समस्या सिर्फ टरढ बढ़ाने से हल नहीं होती। उसे चाहिए उसकी फसल की सुनिश्चित खरीद, समय पर भुगतान और बाजार तक आसान पहुंच। जब तक इन बुनियादी मुद्दों को हल नहीं किया जाएगा, तब तक घोषणाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। युवाओं के संदर्भ में यह बजट और भी अधिक निराशाजनक प्रतीत होता है। आज का युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है, और बड़ी संख्या में राज्य से बाहर जाने को मजबूर है। लेकिन इस बजट में रोजगार सृजन को लेकर कोई ठोस योजना या दृष्टिकोण नजर नहीं आता। न नए उद्योगों की घोषणा, न स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीति, और न ही कौशल विकास के क्षेत्र में कोई बड़ा कदम—यह सब मिलकर यह संकेत देते हैं कि युवा इस बजट की प्राथमिकताओं में कहीं पीछे छूट गए हैं।

विकास के मोर्चे पर भी स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है। सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कोई बड़ा विजन या क्रांतिकारी पहल दिखाई नहीं देती। पहाड़ी राज्यों में ये सुविधाएं केवल विकास का प्रतीक नहीं होतीं, बल्कि जीवन को सुगम बनाने का आधार होती हैं। अगर इन क्षेत्रों में निवेश नहीं बढ़ेगा, तो विकास की गति धीमी ही रहेगी। बजट में कुछ छोटी योजनाओं का जिक्र जरूर किया गया है—जैसे मछली पालन को बढ़ावा देना या सीमित स्तर पर सब्सिडी प्रदान करना। ये पहलें निश्चित रूप से सकारात्मक हैं, लेकिन राज्य की बड़ी आर्थिक चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकतीं। यह ऐसा है जैसे बड़ी समस्या के सामने छोटे उपाय रख दिए जाएं।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 2030 तक वन क्षेत्र को 32 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक अच्छी पहल है, खासकर हिमाचल जैसे पर्यावरण संवेदनशील राज्य के लिए। लेकिन यहां भी वही समस्या सामने आती है—लक्ष्य तो तय कर दिया गया है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना, संसाधन और जवाबदेही का अभाव नजर आता है। समग्र रूप से देखा जाए तो यह बजट एक ऐसे समय में आया है, जब राज्य को मजबूत और दूरदर्शी फैसलों की जरूरत थी। लेकिन इसके बजाय यह बजट संतुलन बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है—जहां सरकार एक तरफ उम्मीदें दिखाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ सीमित संसाधनों के कारण बड़े फैसले लेने से बचती हुई दिखाई देती है।

हिमाचल का आम आदमी अब केवल घोषणाएं सुनकर संतुष्ट नहीं होता। वह अपने जीवन में बदलाव देखना चाहता है—चाहे वह बेहतर सड़क के रूप में हो, अस्पताल में सुविधाओं के रूप में हो या अपने बच्चों के लिए रोजगार के अवसर के रूप में। अगर बजट इन उम्मीदों को पूरा करने में असफल रहता है, तो यह केवल एक औपचारिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश का बजट 2026-27 उम्मीदों और हकीकत के बीच झूलता हुआ नजर आता है। इसमें इरादे तो हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं है; घोषणाएं तो हैं, लेकिन क्रियान्वयन को लेकर भरोसा नहीं है, और शायद यही इस बजट की सबसे बड़ी चुनौती भी है—लोगों का भरोसा जीतना।

अंत में बस इतना ही— जब नीतियों में स्पष्टता और निर्णयों में साहस की कमी हो, तो विकास की राह अपने आप धीमी पड़ जाती है।

राजनीतिज्ञों ने अपने नेताओं के नाम पर शानदार स्मारक बनाए, लेकिन शहीद-ए-आजम भगत सिंह को नजरअंदाज किया: भगवंत सिंह मान

सिटी दर्पण संवाददाता
खटकड़ कलां

शहीद-ए-आजम भगत सिंह के उनके शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दिन देश को शहीदों द्वारा दी गई महान कुर्बानी की याद दिलाता है। उन्होंने लोगों से मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारी की सोच को अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों का सम्मान करने और उनके सपनों का रंगला पंजाब बनाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

देश के महान क्रांतिकारियों की गौरवशाली विरासत को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह अवसर केवल उनकी कुर्बानी को याद करने का ही नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और अन्याय के खिलाफ लड़ने के संकल्प को आगे बढ़ाने का भी है। उन्होंने उनके सपनों के पंजाब और देश की सेवा करने के अपने संकल्प को दोहराया, साथ ही इन स्वतंत्रता सेनानियों को भारत रत्न (सबसे बड़ा सम्मान) न दिए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि शुरूआती वर्षों में देश की बागडोर ऐसे साहसी और प्रगतिशील युवाओं के हाथों में होती तो देश की स्थिति अलग होती।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यह दिन हमें शहीद भगत सिंह द्वारा मातृभूमि के लिए दी गई अद्वितीय कुर्बानी की याद दिलाता है। शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव की शहादत हमें हमेशा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती रहेगी। समाज में मौजूद हर प्रकार की बुराइयों के खिलाफ लड़ना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है।

शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही गरीबी और सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने का एकमात्र स्थायी समाधान है। उन्होंने कहा, शिक्षा समाज की सभी समस्याओं का इलाज है, इसलिए पंजाब सरकार ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत गरीबी या सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन शिक्षा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें मजबूरी और बेबसी के इस चक्र से बाहर निकाल सकती है। इसीलिए, हमारी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सामाजिक परिवर्तन में ज्ञान की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। यदि हम वास्तविक बदलाव चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा, उन्हें सशक्त बनाना होगा और समाज को ऊपर उठाकर गरीबी को खत्म करना होगा। असली बदलाव अस्थायी लाभों से नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और जागरूकता से आएगा।

शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार हमारे महान शहीदों के संकल्पों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम पंजाब की तरक्की और इसके लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध हैं। वह दिन दूर नहीं जब हमारे सामूहिक प्रयासों से पंजाब देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा।

23 मार्च के महत्व के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि केवल 23 मार्च होने के कारण यह दिन खास नहीं है, बल्कि यह एक साधारण दिन असाधारण बन जाता है क्योंकि इसी विशेष दिन देश के तीन वीर सपूतों ने देश के लिए अपनी जवानी और जान कुर्बान की थी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी शहादत ने आजादी के संग्राम में नया जोश भर दिया और उनके अथाह योगदान के कारण 15-16 वर्षों के भीतर लाल किले पर भारतीय तिरंगा फहराया जा सका।

मुख्यमंत्री ने शहीदों की कुर्बानी के निस्वार्थ स्वरूप और लोकतांत्रिक अधिकारों की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह और उनके साथियों ने सत्ता या राजनीतिक लाभ के लिए अपनी जान नहीं दी थी। उनकी कुर्बानी निस्वार्थ थी। उन्हीं की बदौलत आज हमें वोट डालने का अधिकार मिला है। जब हम अपने वोटर आईडी कार्ड को देखते हैं तो हमें अपनी तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो हमें इन शहीदों की महक महसूस होगी। इसलिए हमें अपने वोट का उपयोग समझदारी से करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आजादी से पहले लोग त्योहार तो मनाते थे, लेकिन अंग्रेजों के शासन के कारण हमें वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था। इन शहीदों ने इस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी ताकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना नेता चुन सकें। उन्होंने कहा कि यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को पैसे, प्रभाव या लालच में आकर कभी भी अपना वोट नहीं बेचना चाहिए।

40 साल बाद पंजाब में होगी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप

सिटी दर्पण संवाददाता
जालंधर

पंजाब में बैडमिंटन को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है, क्योंकि राज्य 40 साल बाद राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) ने 38वीं सब-जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप पंजाब को सौंपी है।

जानकारी देते हुए पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव रितिन खन्ना ने बताया कि यह चैंपियनशिप 9 से 12 दिसंबर 2026 तक रायजादा हंसराज बैडमिंटन स्टेडियम,जालंधर में आयोजित होगी। इसमें 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 350 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पंजाब में पिछली बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 1987 में जालंधर में ही आयोजित हुई थी।

खन्ना ने बताया कि पीबीए लगातार बीएआई के संपर्क में था और स्टेडियम की बेहतर सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद ही मेजबानी का अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा कि विजेताओं को कुल 10 लाख रूपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इस चैंपियनशिप में अंडर-13 लड़के और लड़कियों के सिंगल्स और डबल्स मुकाबले होंगे, जो बीएआई अधिकारियों की निगरानी में कराए जाएंगे। खिलाड़ियों, कोच, मैनेजर और अधिकारियों के रहने और खाने की व्यवस्था पीबीए द्वारा की जाएगी।

खन्ना ने कहा कि इस आयोजन से राज्य के उभरते खिलाड़ियों को बड़ा फायदा मिलेगा और उन्हें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को देखने और उनके साथ खेलने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि रायजादा हंसराज बैडमिंटन स्टेडियम में पिछले पांच वर्षों में 1 करोड़ रूपए की लागत से बड़ा सुधार किया गया है। अब यहां 10 कोर्ट, जिम, रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स शॉप और फिजियोथेरेपी सेंटर की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी स्टेडियम का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने डीबीए, जालंधर की अंतरिम कमेटी के काम की सराहना की थी। उल्लेखनीय है कि रितिन खन्ना, जो पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं को खेल में उनके योगदान के लिए पंजाब के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।

भगवंत मान सरकार नंगल में 800 एकड़ से अधिक सरप्लस जमीन के मालिकाना हक निवासियों को देगी : हरजोत सिंह बैंस

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के शिक्षा मंत्री और श्री आनंदपुर साहिब से विधायक श्री हरजोत सिंह बैंस ने आज घोषणा की कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जल्द ही नंगल, तलवाड़ा और आसपास के कस्बों की अतिरिक्त (सरप्लस) जमीन के मालिकाना अधिकार संबंधित दुकानदारों, निवासियों और अन्य काबिज लोगों को देगी, क्योंकि यह जमीन बी.बी.एम.बी. की नहीं बल्कि पंजाब की है। इस फैसले से इलाके के हजारों परिवारों पर दशकों से लटक रही तलवार खत्म हो जाएगी। जल संसाधन विभाग ने 800 एकड़ से अधिक ऐसी जमीन के संबंध में बी.बी.एम.बी. के साथ औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

श्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने जमीनें भी दीं और अपने हाथों से काम भी किया ताकि एक नए स्वतंत्र भारत को पानी और बिजली मिल सके। उन्होंने इस शहर को बनाने में भी अहम योगदान दिया। फिर भी पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से इस प्रोजेक्ट को चलाने वाली अथॉरिटी बी.बी.एम.बी. ने मालिकों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया और उन्हीं लोगों को परेशान किया, जिन्होंने इसे बनाया था।

लोगों को दिए गए भरोसे का जिक्र करते हुए श्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, चार महीने पहले मैं नंगल में प्रभावित परिवारों से मिला था और स्थायी समाधान का वादा किया था। आज वह वादा पूरा हो रहा है। जल संसाधन विभाग ने बी.बी.एम.बी. को औपचारिक नोटिस भेजे हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 800 एकड़ से अधिक अतिरिक्त जमीन पंजाब की संपत्ति है।

कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के पास ऐसी संपत्तियों के लिए लीज नीति बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

गैंगस्टरां ते वार का 62 वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 447 स्थानों पर छापेमारी; 186 गिरफ्तार

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों के तहत शुरू किए गए निर्णायक 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान के 62वें दिन पंजाब पुलिस ने आज प्रदेश भर में गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने गए और मैप किए गए 447 स्थानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि ₹गैंगस्टरां ते वार₹ झ्र पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग है, जो 20 जनवरी, 2026 को पुलिस निदेशक महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शुरू की थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाइयां कर रही हैं।

62वें दिन, पुलिस टीमों ने 186 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 16,497 हो गई है। इसके अलावा 52 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 74 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 3 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं और अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना/जानकारी भी साझा कर सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपना अभियान ₹युद्ध नशेयां विरुद्ध₹ को 387वें दिन भी जारी रखते हुए आज 102 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 6.2 किलोग्राम हेरोइन, 10 किलोग्राम भुक्की, 2160 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 17,113 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही मात्र 387 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 55,152 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 23 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राजी किया है।

अमृतसर में नशा तस्करी मॉड्यूल के दो सदस्य 5 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार

- जांच से पता चला कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तानी तस्करों और सरहद पार से खेप भेजने वाले एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे: डीजीपी गौरव यादव
- आगे की जांच जारी; और गिरफ्तारियों व बरामदगी की उम्मीद

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/अमृतसर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों पर पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (सी.आई.) अमृतसर ने नशा तस्करी करने वाले मॉड्यूल के दो सदस्यों को 5 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार कर इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अमृतसर के खट्टराये खुर्द निवासी मनिंदर सिंह और अमृतसर के फिरवाड़िया निवासी गुरजंट सिंह के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने नशीले पदार्थ के अलावा आरोपियों की हैचबैक हुंडई आई-20 कार (नंबर पीबी10 जीएच 0140) भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल वे खेप लाने-ले जाने के लिए करते थे।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों और सीमा पार से सप्लाई करने वाले एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे।

उन्होंने ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सी.आई. अमृतसर की पुलिस टीमों को पुख्ता सूचना मिली थी कि एक विदेशी व्यक्ति पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में है और वह अपने पंजाब आधारित सहयोगियों–मनिंदर सिंह और गुरजंट सिंह–की मदद से राज्य में नशा तस्करी का नेटवर्क चला रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों को अपने हैंडलर से नशीले पदार्थों की खेप मिली थी, जिसे वे किसी अन्य पार्टी तक पहुंचाने के लिए अपनी आई-20 कार में जिला अमृतसर के अजनाला क्षेत्र के गांव धारीवाल जा रहे थे।

उन्होंने बताया कि इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने इलाके में नाके लगाए और दोनों संदिग्धों को रोककर उनके कब्जे से 5 किलो हेरोइन बरामद की। मामले में आगे की जांच जारी है।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 18 दिनांक 21-03-2026 को पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धाराएं 21, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

राजस्थान सरकार से पंजाब के पानी के उपयोग के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपये की वसूली का दावा दोहराया

आगामी धान की रोपाई से पहले नहर के पानी से सिंचाई 86 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी: बरिंदर कुमार गोयल

सिटी दर्पण संवाददाता
लहरागागा/मूनक

पंजाब के जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने मकरौड़ साहिब में लगभग 6.46 करोड़ रुपये की लागत से घग्गर नदी के किनारे को और मजबूत एवं ऊंचा करने के प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखने के अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार के प्रयासों से पहले 4 करोड़ रुपये की लागत से घग्गर के किनारे मजबूत किए गए थे, जिसके कारण वर्ष 2025 में आए बाढ़ के दौरान भले ही घग्गर नदी लगातार 10 दिनों तक खतरे के निशान से ऊपर बहती रही, लेकिन लोग घग्गर की मार से बच गए।

इससे पहले नहरी पानी की आपूर्ति, नहरों के नवीनीकरण और पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान सरकार से दशकों से बिना भुगतान किए पानी के उपयोग के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपये की वसूली के दावे सहित पिछले चार वर्षों में किए गए कार्यों के बारे में लहरागागा स्थित अपने दफ्तर में मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राजस्थान को या तो पंजाब के जायज बकाए जारी करने चाहिए या पानी लेना बंद कर देना चाहिए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार वर्ष 1960 से फिरोजपुर फीडर के माध्यम से लिए गए पानी के लिए पंजाब को 1.44 लाख करोड़ रुपये की देनदार है, जिसके लिए एक पैसा भी अदा नहीं किया गया है। वर्ष 1920 के दशक में बीकानेर रियासत, संयुक्त पंजाब और ब्रिटिश राज के बीच हुए एक समझौते के अनुसार राजस्थान प्रति एकड़ के आधार पर पानी का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था। वर्ष 1960 तक भुगतान किया जाता था, लेकिन सिंधु जल समझौते के बाद राजस्थान ने लगातार 18,000 क्यूसेक पानी लेने के बावजूद भुगतान करना बंद कर दिया। पंजाब की सिंचाई प्रणाली में हुए क्रांतिकारी बदलावों के बारे में बात करते हुए श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2022 में नहरी सिंचाई से केवल 26.50 प्रतिशत सिंचाई की जाती थी, जो बढ़कर आज 78 प्रतिशत हो गई है और इस वर्ष धान की रोपाई से पहले यह 86 प्रतिशत हो जाएगी। 1,446 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद पहली बार नहरी पानी पहुंचाया गया है।

अप्रैल 2022 से अब तक नहरों की लाइनिंग, मरम्मत, आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे की मजबूती पर 6,700 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो पंजाब के इतिहास में अब तक किया गया सबसे अधिक खर्च है। पंजाब में नहरी पानी से लगभग 75.90 लाख एकड़ में सिंचाई की जा सकती है, जबकि मार्च 2022 तक केवल 20.89 लाख एकड़ को ही नहरी पानी मिल रहा था। लगभग 13,000 किलोमीटर नहरों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसके कारण नहरी पानी अब 58 लाख एकड़ क्षेत्र तक पहुंच रहा है।

लगभग 7,000 खालों को बहाल किया गया है और कुल 15,539 नहरों की सफाई की गई है तथा 18,349 जल मार्गों को पुनर्जीवित किया गया है। पहली बार 545 किलोमीटर तक फैली 101 बंद पड़ी नहरों को पुनर्जीवित किया गया है। इनमें से बहुत सी नहरें 30 से 40 वर्षों से बंद थीं और मिट्टी से भी भरी हुई थीं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केवल बरसाती नालों को पुनर्जीवित करने से 2.75 लाख एकड़ क्षेत्र को नहरी सिंचाई के अंतर्गत लाने में मदद मिली है। पुरानी नहरी प्रणालियों को बहाल करके यह सुनिश्चित किया गया है कि अब खेतों तक 10,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी पहुंच रहा है। वास्तव में पंजाब सरकार ने बिना कोई जमीन प्राप्त किए नई भाखड़ा नहर ही बना दी है क्योंकि इतनी मात्रा में ही भाखड़ा मेन लाइन में पानी बहता है।

सरहिंद नहर को अपग्रेड किया गया है जिससे इसकी क्षमता में 2,844 क्यूसेक का विस्तार हुआ है। सरहिंद और पटियाला जैसी बड़ी नहरों की लाइनिंग करके पानी की उपलब्धता में लगभग 1.5 एमएएफ का विस्तार किया है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण बहाली के बारे में उन्होंने कहा कि बाढ़ की रोकथाम और पानी प्रबंधन के उद्देश्य से 195 कार्यों के लिए राज्य आपदा राहत कोष से 477 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 199 डी-सिल्टिंग साइटों की पहचान की गई है और जंगी स्तर पर नालों की सफाई के लिए नई चेन-माउंटेड मशीनें तैनात की गई हैं। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट, जो 25 वर्षों से अधिक समय से लटका हुआ था, अब 3,394.49 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हो गया है। इससे रणजीत सागर डैम की क्षमता बढ़ेगी और पाकिस्तान के इलाके में बहने वाले हमारे पानी पर रोक लगेगी। पंजाब सरकार द्वारा पूर्ण तर्कसंगत माइनिंग नीति लागू की गई है, जिससे जहां पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों का सुचारू संरक्षण हो रहा है, वहीं राज्य को आर्थिक लाभ भी हो रहा है। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में गांवों एवं शहरों के लोग उपस्थित थे।

संक्षिप्त-समाचार

गुरदासपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव का फैसला महत्वपूर्ण कदमः बिट्टू

नई दिल्ली। रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सोमवार को गुरदासपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सीमा क्षेत्रों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय सरकार की उस स्पष्ट सोच को दशार्ता है, जिसके तहत सीमावर्ती जिलों को सशक्त बनाने और वहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिट्टू ने कहा कि अमृतसर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस (26405/26406) का गुरदासपुर में ठहराव शुरू होने से स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा मिलेगी। इससे न केवल यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय पर गुरदासपुर के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दीं।

किन्नर गुरु माँ मधु की बरसी पर अखंड पाठ का भोग डाला

चंडीगढ़। किन्नर डेरा सेक्टर 26 द्वारा सोमवार को बापूधाम, सेक्टर 26 के गुरुद्वारा साहिब में किन्नर गुरु माँ मधु की 11वीं बरसी पर अखंड पाठ का भोग डाले गए। इस मौके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। जय माता किन्नर मंदिर की पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर माँ कमलीनंद गिरी जी अंतर्राष्ट्रीय किन्नर व जूना अखाड़ा ने बताया कि किन्नर गुरु माँ मधु की 11वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर बापूधाम, गुरुद्वारा साहिब में 21 मार्च को अखंड पाठ साहिब आरंभ किया गया था और आज 23 मार्च को पाठ का भोग डाला गया। इस मौके किन्नर समाज के लोगों ने गुरु माँ को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने बताया कि गुरु माँ बेहद स्नेही, मिलनसार और मददगार महिला था। उन्होंने कभी किसी का दिल नही दुखाया, बल्कि सभी की मदद करने को वो सदैव तत्पर रहती है। चंडीगढ़ व आसपास के एरिया में किन्नर समाज को पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया।

वीवो ने वाय51 प्रो 5जी पेश किया

चंडीगढ़ । वीवो ने अपनी लोकप्रिय वाय-सीरीज का विस्तार करते हुए वीवो वाय51 प्रो लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो भरोसेमंद परफॉर्मेंस, मजबूत बैटरी लाइफ और स्मार्ट फीचर्स को एक स्टाइलिश पैकेज में चाहते हैं। रोजमर्रा के उपयोग और लंबे समय तक चलने वाली पावर पर फोकस करते हुए, यह डिवाइस सक्षम हार्डवेयर और स्मार्ट सॉफ्टवेयर का बेहतरीन संतुलन पेश करता है। इस डिवाइस के केंद्र में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 टर्बो चिपसेट दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम, एंटरटेनमेंट और गेमिंग के लिए भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है। इसकी एफिशिएंट आर्किटेक्चर मल्टीटास्किंग और लंबे गेमिंग सेशन्स को आसानी से संभालती है, साथ ही थर्मल एफिशिएंसी भी बनाए रखती है। वीवो ने बैटरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी दी है, जो बैटरी हेल्थ को लंबे समय तक बनाए रखती है और 6 साल तक बेहतर बैटरी परफॉर्मेंस का भरोसा देती है। साथ ही, रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट से आप अन्य डिवाइसेज को भी चार्ज कर सकते हैं। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें 50एमपी एचडी वाइड-एंगल मेन कैमरा दिया गया है, जो अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन्स में शानदार और शार्प तस्वीरें कैप्चर करता है। एआई द्द आधारित फीचर्स फोटो को बेहतर क्लैरिटी और कलर बैलेंस देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन फोटो और वीडियो को स्टेबल बनाए रखता है। यह स्मार्टफोन पहली बार वीवो की वाई सीरीज में ओरिजिनओएस 6 लेकर आता है, जिसमें कई इंटेलिजेंट एआई फीचर्स शामिल हैं, जो स्मूद और प्रोडक्टिविटी-फोकस्ड परफॉर्मेंस देते हैं। यह सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एआई-ड्रिवन टूल्स के साथ आता है, जो रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

आईएचसीएल ने जिम्मेदार पर्यटन को मजबूत किया, पाथ्या के चार वर्ष पूरे होने पर भारत एकसाथ वॉकाथॉन का आयोजन

चंड़ीगढ़। इंडियन होटल्स कंपनी (आईएचसीएल), भारत की सबसे बड़ी आतिथ्य कंपनी, अपने ईएसजी+ ढांचे पाथ्या के तहत स्थिरता और सामाजिक प्रभाव को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है। अपने चौथे वर्ष के अवसर पर, आईएचसीएल ने भारत एकसाथ वॉकाथॉन के माध्यम से सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। यह 3 किमी की समावेशी वॉक थी, जिसमें सहयोगियों, उनके परिवारों, स्थानीय साझेदारों, विक्रेताओं और समुदाय के लोगों ने 14 देशों के 200 से अधिक स्थानों पर भाग लिया। इस वॉकाथॉन के माध्यम से जुटाई गई राशि ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट (टीपीएसडब्ल्यूटी) को समर्थन प्रदान करती है, जो सामाजिक प्रभाव के प्रति आईएचसीएल के दृष्टिकोण को और सुदृढ़ करती है। गौरव पोखरियाल, एग्जीक्यूटिव वाईस प्रेसिडेंट झ्र ूमन रिसोर्सेज, आईएचसीएल ने कहा कि वपाथ्या हमारे इस विश्वास को दशार्ता है कि साझा मूल्य तब उत्पन्न होता है जब स्थिरता को संगठन की रणनीति और संचालन में गहराई से शामिल किया जाता है। वर्षो में, पाथ्या एक प्रतिबद्धता से विकसित होकर एक समग्र ढांचे में बदल गया है, जो पर्यावरणीय प्रदर्शन, सामाजिक प्रभाव, शासन और विरासत संरक्षण जैसे क्षेत्रों में हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन करता है।

आपकी योजना आपके द्वार, कार्यक्रम समावेशी विकास का आधार है : देवेश मौदगिल

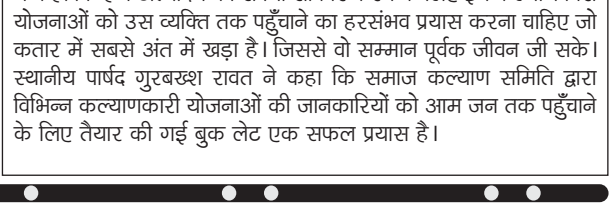

चंडीगढ़। फेडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन्स, सेक्टर 40 द्वारा इसी सेक्टर में स्थित सामुदायिक केंद्र में आपकी योजना-आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना और नागरिकों तक उनकी प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करना था। फेडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन्स सेक्टर 40 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दलविंदर सैणी ने बताया के इस अवसर पर चंडीगढ़ के पूर्व मेयर एवं प्रशासक सलाहकार समिति के सदस्य देवेश मौदगिल मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे उनके साथ स्थानीय पार्षद गुरबख्श रावत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। अपने संबोधन में पूर्व मेयर देवेश मौदगिल ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज की वास्तविक शक्ति उसके सबसे कमजोर और वंचित वर्गों के समग्र उत्थान में निहित होती है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, बच्चों की सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा तथा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न पहलों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि ये सभी योजनाएँ न केवल गरिमा और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करती हैं, बल्कि समाज में समान अवसर और समावेशी विकास की भावना को भी प्रोत्साहित करती हैं। देवेश मौदगिल ने समाज कल्याण विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए विभाग द्वारा की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। इनमें मुख्य तौर पर बेटियों के लिए 'शगुन योजना के तहत ₹31,000 की सहायता राशि, मजदूर भवन के निर्माण में हुई प्रगति, सरकारी अस्पताल सेक्टर 16 में शुरू की गई शाम की ओपीडी (आउटपेशेंट सेवाएँ), विभिन्न पेंशन में वृद्धि के प्रस्ताव और सेक्टर-49 में एक नए वरिष्ठ नागरिक गृह के निर्माण की योजनाएँ शामिल हैं। चंडीगढ़ के पूर्व महापौर, दवेश मौदगिल ने कहा कि हमें अंत्योदय का सपना साकार करने के लिए इन कल्याणकारी योजनाओं को उस व्यक्ति तक पहुँचाने का हरसंभव प्रयास करना चाहिए जो कतार में सबसे अंत में खड़ा है। जिससे वो सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। स्थानीय पार्षद गुरबख्श रावत ने कहा कि समाज कल्याण समिति द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियों को आम जन तक पहुँचाने के लिए तैयार की गई बुक लेट एक सफल प्रयास है।

तेहरान में भीषण विस्फोट, इजराइल पर मिसाइलों से हमला, लेबनान का कासमीयेह पुल ध्वस्त

खुर्रमबाद में ब्लैकआउट, तेहरान के पूर्वी हिस्से में भारी तबाही

दुनिया पर गहराया ऊर्जा संकट

एजेंसी (हि.स.)

तेहरान/तेल अवीव/बेरूत

ईरान की राजधानी तेहरान में सोमवार अब से कुछ देर पहले भीषण विस्फोट हुए हैं। इजराइल का आसमान मिसाइलों की तेज रफ्तार से चमक उठा हुआ है। लेबनान में कासमीयेह पुल ध्वस्त कर दिया गया है। इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से छिड़े युद्ध के थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस युद्ध से तेल और गैस का संकट गहरा गया है। दुनिया के तमाम हिस्सों में त्राहिमाम-त्राहिमाम मचा हुआ है।

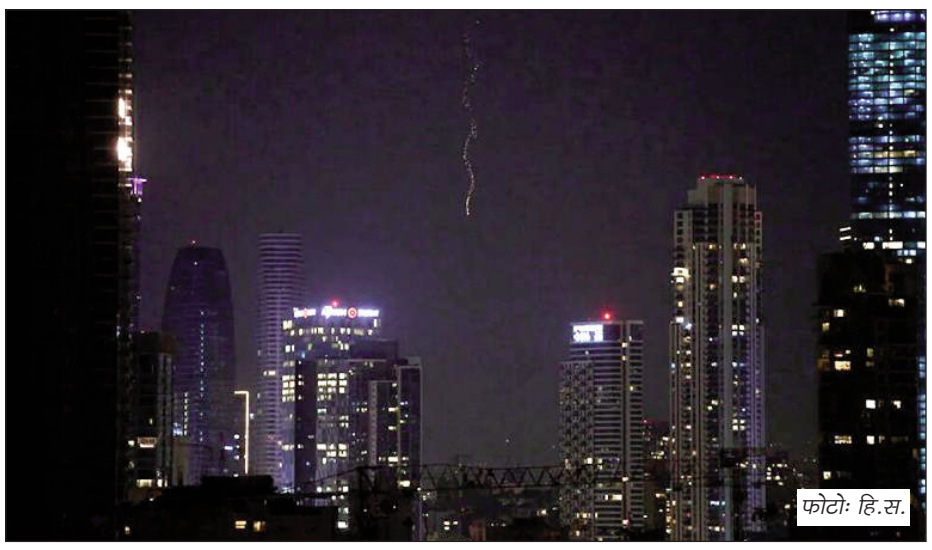
फोटोः हि.स.

अल जजीरा चैनल और द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की राजधानी तेहरान के पूर्वी हिस्से में इस युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। राजधानी तेहरान का पूर्वी हिस्सा इससे हिल गया है। हमले की तीव्रता को देखते हुए हवाई रक्षा तंत्र (एयर डिफेंस सिस्टम) को सक्रिय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका-इजराइल ने एकीकृत हमला किया है।

तेहरान को दहलाने से पहले हवाई हमले के बाद व्यापक तबाही हुई है। मिसाइलों और रॉकेट से किए गए हमले के बाद इलाके में ब्लैक आउट हो गया है। कुछ इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक अहम पुल को निशाना बनाया है। हमले में कासमीयेह पुल उड़ गया है। इससे यातायात और मानवीय सहायता की पहुंच बाधित हो गई। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस हमले की निंदा की है।

इजराइल का कहना है कि इस पुल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह आतंकी करते थे। हिजबुल्लाल के हमलों को रोकने के लिए इसे नष्ट करना जरूरी था। आईडीएफ ने कहा है कि ईरान की इजराइली डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने कहा कि ईरान पर हमले शुरू होने वाले हैं। इस बीच बताया गया है कि ईरान के खुर्रमबाद में क्लस्टर मिसाइलों से मध्य इजराइल में हुए नुकसान के बाद तेहरान पर हमला किया गया। ईरान के हमले में कोई घायल नहीं हुआ है।

नेपाल में बालेन्द्र की पहली कैबिनेट बैठक में 1170 राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द करने की तैयारी

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

फोटोः हि.स.

बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में बनने वाली सरकार ने राज्य के विभिन्न निकायों में की गई कुल 1,170 राजनीतिक नियुक्तियों को एक साथ रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासनिक तंत्र में सुधार लाने की योजना के तहत सरकार गठन के तुरंत बाद शाह का पहला कदम पिछले शासनकाल में की गई नियुक्तियों को रद्द करना होगा। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के वरिष्ठ नेता शाह 27 मार्च को प्रधानमंत्री पद के लिए शपथग्रहण करने वाले हैं। उसी दिन वे मंत्रिमंडल गठन करने की तैयारी में हैं। संवैधानिक निकायों, सार्वजनिक संस्थानों, कूटनीतिक मिशनों और विभिन्न बोर्डों में राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां होती रही हैं। इन सबका विवरण एकत्र किया जा रहा है। पार्टी के केंद्रीय सदस्य एवं सांसद पुकार बम के अनुसार, शाह के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद होने वाली मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में ही इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा।

पार्टी प्रवक्ता मनीष झा के अनुसार, नई सरकार बनने से पहले ही ऐसे पदों पर बैठे लोगों से नैतिक आधार पर स्वेच्छा से इस्तीफा देने का आग्रह किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि राज्य तंत्र को ह्लकार्यकर्ता भर्ती केंद्रह्व बनने से रोकने के अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि केवल कार्यकताओं के पालन-पोषण के उद्देश्य से की गई नियुक्तियों को रद्द किया जाएगा। उनका कहना है, ह्लयदि किसी व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि है लेकिन वह सक्षम है, तो उसकी नियुक्ति उचित हो सकती है। लेकिन केवल अनावश्यक रूप से कार्यकताओं को लाभ पहुँचाने के लिए राज्य पर बोझ डालने वाली नियुक्तियों को समाप्त किया जाएगा। सरकार में आने के बाद इनका पुनरावलोकन किया जाएगा ह्ल झा के अनुसार, ऐसी नियुक्तियों की संख्या 1,170 है। उन्होंने यह भी कहा, ह्लकुछ आयोग और निकाय तो हमें आवश्यक ही नहीं लगते, वे करदाताओं के पैसे पर बोझ मात्र हैं। अगर संबंधित लोग अभी स्वेच्छा से पद छोड़ दें तो बेहतर होगा ह्ल

फिलहाल पार्टी ने यह सार्वजनिक नहीं किया है कि किन-किन निकायों या पदों को खाली कराया जाएगा। नेताओं के अनुसार, इस विषय पर अभी और चर्चा व तैयारी बाकी है, इसलिए नाम तुरंत सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। कुछ मामलों में केवल पदाधिकारी बदलने के बजाय पद या संस्थान को ही समाप्त किया जा सकता है। जेन-जी आंदोलन के बाद हुए चुनाव में लगभग दो-तिहाई जनमत प्राप्त कर सरकार बनाने की तैयारी में जुटी पार्टी ने सत्ता में आते ही लोकप्रिय कदम उठाने की योजना बनाई है। जनता को स्पष्ट रूप से दिखने वाले कार्यों के लिए बालेन्द्र शाह ने विभिन्न नियुक्तियों की समीक्षा और निरस्तीकरण को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। इस कदम से संवैधानिक निकायों से लेकर सरकारी संस्थानों तक के प्रमुख और सदस्य सीधे प्रभावित हो सकते हैं। नेपाल में एंटी करप्शन ब्यूरो, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और निर्वाचन आयोग जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हैं जहां राजनीतिक नियुक्तियां होती आई हैं।

बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेस-वे पर हादसा, चार की मौत

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

बेंगलुरु

बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेस-वे पर सोमवार तड़के हुए हादसे में चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि केरलम के एक निजी ट्रैवल्स कंपनी की बस केरलम से बेंगलुरु की ओर आ रही थी। इसी दौरान रामनगर जिले के चन्नापटना तालुक के पुट्टप्पनदोड्डी के पास बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चार यात्रियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान केरलम निवासी मोहम्मद परान (22), रफीज (45) तथा बेंगलुरु निवासी राशीद (45) और साकिर (27) के रूप में हुई है। पुलिस का मानना है कि हो सकता है चालक को झपकी आ गई हो। दुर्घटना में कई यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जेन जी आंदोलन की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई नई सरकार के गठन के बाद

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

फोटोः हि.स.

एक सप्ताह बाद यानी 27 मार्च को बालेन्द्र शाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना तय हो चुका है। ऐसे में जेन जी आंदोलन की जांच प्रतिवेदन को लागू करना या सार्वजनिक करना अब उन्हीं की जिम्मेदारी होगी।

अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार ने उक्त प्रतिवेदन को सार्वजनिक न करने का निर्णय लिया है। अंतरिम प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार रामबहादुर रावल ने कहा कि वर्तमान सरकार अपने हिस्से का काम पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा, ह्लइस सरकार ने प्रतिवेदन को आगे बढ़ा दिया है, बाकी काम आने वाली सरकार पूरा करेगी ह्ल रविवार को हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने जांच आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने का निर्णय लिया था। हालांकि, रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद भी आगे की कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ाई गई है।

नेपाल सरकार के मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल ने कहा, ह्लप्रतिवेदन स्वीकार कर लिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। इसे सार्वजनिक करना है या नहीं, यह निर्णय कैबिनेट का होता है। जांच आयोग गठित कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने और उसे लागू करने का वादा करने वाली सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली सरकार अब विदाई के चरण में है। इस सरकार ने रिपोर्ट के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निर्वाचित सरकार को सौंप दी है।

रिपोर्ट स्वीकार करने के एक सप्ताह बाद भी न तो पूर्व घोषणा के अनुसार इसे सार्वजनिक किया गया है और न ही कार्यान्वयन के लिए संबंधित निकायों को भेजा गया है। फिलहाल रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में ही रखी हुई है। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और लागू करने की मांग जेन जी आंदोलन के नेताओं द्वारा लगातार की जा रही है। जेन जी की अगुवा रक्षा बम ने सुशीला कार्की से अपील की है कि वह रिपोर्ट सार्वजनिक करें और 8 और 9 सितंबर 2025 को हुई घटनाओं में संलिप्तता स्पष्ट करें।

सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक न होने से उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए रिपोर्ट को सार्वजनिक करना आवश्यक है।

संक्षिप्त-समाचार

पश्चिम एशिया में जारी जंग के कारण औंधे मुंह गिरा रुपया

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारतीय मुद्रा रुपये की कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को भारतीय मुद्रा ने एक बार फिर ऑल टाइम लो का नया रिकॉर्ड बनाया। कच्चे तेल की कीमत में आई तेजी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी, डॉलर की मजबूती और विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार में अंधाधुंध तरीके से बिकवाली कर अपना पैसा निकालने की वजह से रुपये पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी दबाव की वजह से इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा डॉलर की तुलना में 93.95 रुपये प्रति डॉलर के अभी तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। हालांकि इसके बाद इसकी स्थिति में मामूली सुधार भी हुआ, जिसके कारण सुबह 10:30 बजे भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 93.92 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रही थी। इसके पहले पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय मुद्रा 93.71 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने सोमवार को के कारोबार की शुरूआत भी गिरावट के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने सोमवार को सुबह डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की कमजोरी के साथ 93.83 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरूआत की थी। सोमवार को का कारोबार शुरू होने के बाद रुपये की स्थिति में मामूली सुधार भी आया, जिससे ये 93.79 के स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने लगातार बिकवाली कर अपने पैसे की निकासी शुरू कर दी, जिससे मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग तेज हो गई। ऐसा होने पर रुपये की कीमत भी तेजी से लुढ़कने लगी।

ग्लोबल मार्केट से जबरदस्त कमजोरी के संकेत एशिया में भी चौतरफा बिकवाली का दबाव

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के और बढ़ जाने तथा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर्स की आवाजाही को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के कारण ग्लोबल मार्केट में दबाव बना हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान दो प्रतिशत तक की गिरावट का शिकार हो गए। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी सोमवार को कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रहा। वहीं एशियाई बाजार भी सोमवार को बड़ी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल होने की आशंका की वजह से अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान डर का माहौल बना रहा। इस डर के कारण वॉल स्ट्रीट के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। एस एंड पी 500 इंडेक्स 100.01 अंक यानी 1.51 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 6,506.48 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 443.08 अंक यानी 2.01 प्रतिशत टूट कर 21,647.61 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स सोमवार को फिलहाल 0.17 प्रतिशत फिसल कर 45,504.02 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार बिकवाली होती रही। एफटीएसई इंडेक्स 145.17 अंक यानी 1.46 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 9,918.33 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 142.25 अंक यानी 1.86 प्रतिशत की गिरावट के साथ 7,665.62 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया।

पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की युवक की हत्या, दोनों गिरफ्तार

बाड़मेर। बालोतरा जिले के गिडा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां एक युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी। पुलिस ने मामले का पदार्फाश करते हुए आरोपित पत्नी और उसके सरकारी शिक्षक प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, मलवा गोयलान निवासी 23 वर्षीय महेंद्र मेघवाल की शादी करीब चार साल पहले बागूंडी निवासी अनु देवी से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। सामाजिक स्तर पर कई बार समझौते की कोशिश भी की गई, लेकिन पति-पत्नी के संबंध सामान्य नहीं हो पाए। जांच में सामने आया कि अनु देवी अपने पति से प्रेम नहीं करती थी और किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने की बात भी कहती थी, जिससे दोनों के बीच विवाद लगातार बढ़ता गया। घटना 20 मार्च की रात की है, जब एक बार फिर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद अनु देवी ने अपने प्रेमी अमराराम को फोन कर घर बुला लिया। अमराराम तिलवाड़ा का निवासी है और चिड़िया पंचायत के बारूपलों की बस्ती स्थित एक प्राथमिक स्कूल में ग्रेड थर्ड शिक्षक के पद पर कार्यरत है। दोनों ने मिलकर महेंद्र का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अगली सुबह जब महेंद्र काफी देर तक घर से बाहर नहीं निकला तो पास में रहने वाले परिजनों को शक हुआ। जब वे घर पहुंचे तो अनु देवी ने बताया कि महेंद्र कमरे में सो रहा है। परिजन जब कमरे में गए तो महेंद्र का शव चारपाई पर पड़ा मिला। उसके गले पर चोट के निशान देखकर हत्या की आशंका जताई गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

आग लगने से चार घर और दो दुकानें जलकर राख

दार्जिलिंग। जिले के कर्सियांग महकमा के मंगपू में सोमवार तड़के भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग में चार घर और दो दुकानें जलकर राख हो गये। जानकारी के अनुसार, चौरस्ता इलाके में एक घर से आग की शुरूआत हुई और देखते ही देखते पास के घरों और दुकानों में फैल गई। पहाड़ों की तेज हवाओं के कारण आग ने जल्दी ही विकराल रूप ले लिया, जिससे लकड़ी और टिन से बने मकान तेजी से जलकर खाक हो गए। इस हादसे में चार घर और दो दुकानें पूरी तरह जल गई। घरों का सामान, जरूरी कागजात, नकदी और दुकानों का माल सब कुछ राख हो गया। नुकसान का आंकड़ा लाखों में बताया जा रहा है। आग लगते ही स्थानीय लोगों ने बुझाने की कोशिश की और दमकल को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुरूआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे है और प्रभावित परिवारों की मदद की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

सोना और चांदी की कीमत में मामूली गिरावट

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में सोमवार को शुरूआती कारोबार के दौरान सांकेतिक कमजोरी का रुख नजर आ रहा है। सोमवार के दिन कीमत में आई गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना सोमवार को 1,45,960 रुपये से लेकर 1,46,110 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना सोमवार को 1,33,790 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,33,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर बिक रही है।

दिल्ली में सोमवार को 24 कैरेट सोना 1,46,110 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,940 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,45,960 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,33,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,46,010 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,840 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना सोमवार को 1,45,960 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,33,790 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,45,960 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,33,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,33,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना सोमवार को 1,46,110 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,33,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,33,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,46,110 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,33,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोमवार को सोने के भाव में मामूली कमजोरी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,45,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला टिपको इंजीनियरिंग का आईपीओ, एक अप्रैल को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली। इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी टिपको इंजीनियरिंग इंडिया का 60.55 करोड़ रुपये का आईपीओ सोमवार को सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 25 मार्च तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 27 मार्च को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 30 मार्च को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर एक अप्रैल को बीएसई के एनएसई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 84 रुपये से लेकर 89 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1,600 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 3,200 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,84,800 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 68,03,200 शेयर जारी हो रहे हैं। इनमें 39 करोड़ रुपये के 44,27,200 नए शेयर और 12 करोड़ रुपये के 13,55,200 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे जा रहे हैं। वहीं 10,20,800 शेयर मार्केट मेकर्स के लिए रिजर्व किए गए हैं।

स्टॉक मार्केट में इनोविजन की कमजोर लिस्टिंग पहले ही दिन आईपीओ निवेशक निराश

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

टोल मैनेजमेंट और मैनपावर सर्विस देने वाली कंपनी इनोविजन के शेयरों ने सोमवार को स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट के साथ एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 519 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। सोमवार को बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 466 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर 467.70 रुपये के स्तर पर हुई। इस तरह लिस्टिंग के साथ ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को लगभग 10 प्रतिशत का नुकसान हो गया। कमजोर लिस्टिंग के बाद बिकवाली के दबाव की वजह से इस शेयर में और गिरावट आ गई, जिसके कारण सुबह 11 बजे तक का कारोबार होने के बाद कंपनी के शेयर 384.80 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इस तरह अभी तक के कारोबार के बाद कंपनी के आईपीओ निवेशकों 134.20 रुपये प्रति शेयर यानी 25.86 प्रतिशत का नुकसान हो चुका था। इनोविजन का आईपीओ 10 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। पहले इसकी क्लोजिंग की तारीख 12 मार्च और लिस्टिंग की तारीख 17 मार्च तय की गई थी, लेकिन 12 मार्च तक काफी कम सब्सक्रिप्शन आने के कारण क्लोजिंग को बढ़ा कर 17 मार्च और लिस्टिंग की तारीख को बढ़ा कर 20 मार्च कर दिया गया। इसके साथ ही इनवेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए कंपनी ने आईपीओ के प्राइस बैंड और इश्यू साइज में भी बदलाव किया। इस इश्यू के लिए पहले तय 521 रुपये से लेकर 548 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड को बदल कर 494 रुपये से लेकर 519 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया।

शुरूआती कारोबार में शेयर बाजार पर जबरदस्त दबाव, सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

सप्ताह के पहले दिन ही घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को शुरूआती कारोबार के दौरान बड़ी गिरावट का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को के कारोबार की शुरूआत भी कमजोरी के साथ हुई थी। बाजार खुलते ही मार्केट में बने निगेटिव सेंटीमेंट्स की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की कमजोरी और बढ़ गई। हालांकि थोड़ी देर बाद खरीदारों ने लिवाली का जोर बनाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी इस कोशिश से भी बाजार पर ज्यादा असर नहीं पड़ सका। सुबह 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 2.22 प्रतिशत और निफ्टी 2.25 प्रतिशत की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे।

सोमवार को प्रातः 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से ओएनजीसी के शेयर 0.87 प्रतिशत, टीसीएस के शेयर 0.18 प्रतिशत और एचसीएल टेक्नोलॉजी के शेयर 0.76 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, श्रीराम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचडीएफसी लाइफ के शेयर 4.18 प्रतिशत से लेकर 2.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,781 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 240 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 2,541 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से तीन शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे। दूसरी ओर 27 शेयर बिकवाली के दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से तीन शेयर हरे निशान में और 47 शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे थे।

सातारा जिप चुनाव | **एसपी तुषार दोशी पर गिरी गाज**

पुलिस ज्यादती की जांच की जाएगी: मुख्यमंत्री

एजेंसी (हि.स.)

मुंबई

फोटोः हि.स.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि सातारा जिला परिषद चुनाव में हुई पुलिस ज्यादती की गहन छानबीन करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस आज विधान सभा में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से उपस्थित किए गए सातारा जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में की गई पुलिस ज्यादती के मुद्दे का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले की छानबीन कर सत्य आम जनता के सामने लाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद को बताया कि सातारा जिला परिषद के अध्यक्ष पद चुनाव के एक दिन पहले वहां के दो नगरसेवकों के विरुद्ध दस साल पुराने मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया। इसके बाद इन दोनों नगरसेवकों को अध्यक्ष पद के चुनाव में शामिल होने से रोका गया। यह सब सातारा जिले के अधीक्षक तुषार दोशी के नेतृत्व में किया गया और मंत्री के साथ भी मारपीट की गई। एकनाथ शिंदे ने कहा कि देश में लोकशाही में किसी को मतदान से रोकने की ऐतिहासिक घटना सातारा जिला परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हुई है। इससे पहले कैदियों को मतदान देने की व्यवस्था देश में की गई है। उन्होंने इस मामले की गहन छानबीन की मांग की।

इससे पहले विधान परिषद में शिवसेना शिंदे समूह के नेता और मंत्री शंभूराजे देसाई ने सातारा जिला परिषद में अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान पुलिस ज्यादती का मुद्दा उपस्थित किया था। इसके बाद विधान परिषद की उप सभापति नील गोरहे ने सातारा जिला पुलिस अधीक्षक को तत्काल निलंबित किए जाने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। हालांकि इस मुद्दे पर विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की है।

हॉकी इंडिया ने की '8वें वार्षिक पुरस्कार 2025' के लिए नामित खिलाड़ियों की घोषणा

27 मार्च को सजेगा भारतीय हॉकी का मंच, दिल्ली में होगा सितारों का महासंगम

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

हॉकी इंडिया ने सोमवार को '8वें वार्षिक पुरस्कार 2025' के लिए नामांकित खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। यह पुरस्कार समारोह 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें वर्ष 2025 के दौरान भारतीय हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान देने वाले खिलाड़ियों व अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा।

फोटोः हि.स.

इस समारोह के प्रमुख पुरस्कारों में 'हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार' शामिल है, जो पुरुष और महिला वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इसके अलावा उभरती प्रतिभाओं को 'हॉकी इंडिया जुगराज सिंह उभरते खिलाड़ी (पुरुष अंडर-21)' और 'हॉकी इंडिया असुंता लकड़ा उभरती खिलाड़ी (महिला अंडर-21)' पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।

विभिन्न पोजीशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 'हॉकी इंडिया बलजीत सिंह वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर', 'हॉकी इंडिया परगट सिंह वर्ष के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर', 'हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर' और 'हॉकी इंडिया धनराज पिल्लै वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड' पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इन आठ श्रेणियों में कुल 32 खिलाड़ियों को अंतिम सूची में शामिल किया गया है।

इसके अलावा समारोह में 'हॉकी इंडिया अध्यक्ष उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार', 'जमन लाल शर्मा अमूल्य योगदान पुरस्कार', अंपायर और तकनीकी अधिकारियों के लिए विशेष सम्मान, तथा सर्वश्रेष्ठ सदस्य इकाई पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।

इस दौरान 2025 में एशिया कप राजगीर (बिहार) में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम और एफआईएच हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप तमिलनाडु में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय जूनियर पुरुष टीम को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सदस्य इकाइयों को भी मान्यता दी जाएगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा, यह भारतीय हॉकी के लिए महत्वपूर्ण वर्ष है और ऐसे में पिछले वर्ष के बेहतरीन प्रदर्शन को पहचान देना जरूरी है। ये पुरस्कार खिलाड़ियों और अधिकारियों के समर्पण और उपलब्धियों को सम्मानित करते हैं। वहीं महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा, ये पुरस्कार खिलाड़ियों, कोचों, अधिकारियों और सदस्य इकाइयों के सामूहिक प्रयासों को मान्यता देते हैं, जिन्होंने भारतीय हॉकी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

नामांकित खिलाड़ी इस प्रकार हैं:

वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर (बलजीत सिंह पुरस्कार): प्रिंस दीप सिंह, कृष्ण बहादुर पाठक, बिचु देवी खारीबाम, सूरज करकेरा **वर्ष के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर (परगट सिंह पुरस्कार):** संजय, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, हरमनप्रीत सिंह। **वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर (अजीत पाल सिंह पुरस्कार):** हार्दिक सिंह, सुमित, राज कुमार पाल, नीलकांत शर्मा। **वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड (धनराज पिल्लै पुरस्कार):** सुखजीत सिंह, अभिषेक, नवनीत कौर, शिलानंद लकड़ा। **उभरती खिलाड़ी (महिला अंडर-21, असुंता लकड़ा पुरस्कार):** साक्षी राणा, ज्योति सिंह, सुनेलिता टोप्पो, कनिका सिवाच **उभरते खिलाड़ी (पुरुष अंडर-21, जुगराज सिंह पुरस्कार):** प्रिंस दीप सिंह, मनमीत सिंह, अनमोल एक्का, अर्शदीप सिंह। **वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी (बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार):** नवनीत कौर, सलीमा टेटे, लालरेमसियामी, सविता। **वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी (बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार):** हार्दिक सिंह, सुखजीत सिंह, संजय, अभिषेक।

कराबाओ कप: मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को हराकर दो साल बाद जीता पहला खिताब

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
लंदन

कराबाओ कप के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को आर्सेनल को 2-0 से हराकर दो साल बाद खिताब अपने नाम किया। वेम्बली मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में निको ओ'रेली ने दूसरे हाफ में दो गोल कर टीम को जीत दिलाई। प्रीमियर लीग में शीर्ष पर चल रही आर्सेनल इस मुकाबले में मजबूत दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन सिटी के सामने वह पूरी तरह फीकी साबित हुई। इस जीत के साथ सिटी ने इस प्रतियोगिता का नौवीं बार खिताब जीता। टीम के मुख्य प्रशिक्षक पेप गार्डियोला के लिए यह जीत बेहद खास रही। उनके मार्गदर्शन में टीम ने पांचवीं बार यह खिताब जीता और वह इस प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे सफल प्रशिक्षक बन गए। उन्होंने जोस मोरिन्हो, एलेक्स फर्ग्यूसन और ब्रायन क्लफ के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

पहले हाफ में मुकाबला बराबरी का रहा और कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में सिटी ने खेल की रफ्तार बढ़ाई और 60वें मिनट में आर्सेनल के गोलकीपर केपा अरिजाबालागा की गलती का फायदा उठाते हुए ओ'रेली ने पहला गोल दागा। इसके चार मिनट बाद सिटी ने बढ़त दोगुनी कर दी। दाईं ओर से बने शानदार मूव पर मैथियस नुनेस के सटीक पास को ओ'रेली ने हेडर के जरिए गोल में बदल दिया। आर्सेनल के खिलाड़ियों में निराशा साफ दिखी। बेन व्हाइट को विरोधी खिलाड़ी पर फाउल करने के कारण पीला कार्ड भी मिला। अंत में आर्सेनल ने वापसी की कोशिश की, लेकिन गैब्रियल का शॉट क्रॉसबार से टकरा गया। मैच के बाद बर्नार्डो सिल्वा ने ट्रॉफी उठाई, जबकि आर्सेनल के अधिकांश समर्थक मैदान छोड़ चुके थे। सिटी के प्रशंसकों ने जीत का जमकर जश्न मनाया। गौरतलब है कि सिटी पिछले वर्ष कोई खिताब नहीं जीत सकी थी, लेकिन इस जीत से उसने दिखा दिया कि वह अब भी खिताब की मजबूत दावेदार है।

मियामी ओपन 2026 में बड़ा उलटफेर, वर्ल्ड नंबर-1 अल्कराज तीसरे दौर से बाहर

एजेंसी (हि.स.)
मियामी

मियामी ओपन 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां विश्व नंबर-1 कार्लोस अल्कराज को रविवार को तीसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा ने कड़े मुकाबले में तीन सेटों में हराकर बाहर कर दिया। 22 वर्षीय अल्कराज, जिन्होंने इसी साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया था, इस सीजन में अब तक 17-2 के रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। इससे पहले वह पिछले सप्ताह इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में डेनियल मेदवेदेव से हार चुके थे।

फोटोः हि.स.

मुकाबले में कोर्डा ने दूसरे सेट में 5-4 पर मैच सर्व करने का मौका बनाया था, लेकिन अल्कराज ने शानदार वापसी करते हुए लगातार पांच गेम जीत लिए। हालांकि, 25 वर्षीय कोर्डा ने तीसरे सेट में खुद को संभालते हुए 6-3, 5-7, 6-4 से जीत दर्ज की। मैच के बाद अल्कराज ने कहा, यह एक कठिन मुकाबला था। कोर्डा ने शानदार खेल दिखाया और अहम मौकों पर मुझसे बेहतर प्रदर्शन किया।

वहीं कोर्डा ने अपनी जीत पर कहा, आज के मैच में सबसे अहम चीज आत्मविश्वास थी। मैंने हर शॉट पर भरोसा रखा और अंत में सफलता मिली। एटीपी टूर के अनुसार, विश्व रैंकिंग में 36वें स्थान पर मौजूद कोर्डा, अल्कराज को हराने वाले सबसे कम रैंक वाले खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले यह कारनामा पिछले साल डेविड गोफिन ने किया था। अब कोर्डा का अगला मुकाबला क्वालीफायर मार्टिन लैंडालूस से होगा, जिन्होंने करेन खाचानोव को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। अन्य मुकाबलों में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और टॉमी पॉल भी चौथे दौर में पहुंच गए हैं। इसके अलावा जीरी लेहेका, वैलेंटिन वाचेरोट और टॉमस मार्टिन एचेवेरी ने भी अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले चरण में प्रवेश किया।

पीसीबी अध्यक्ष नकवी की पीसीबी छोड़ आईपीएल में जाने वाले खिलाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की धमकी

कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी की नई गीदड़भभकी सामने आई है। उन्होंने उन खिलाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, जिन्होंने आखिरी मिनट में पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) छोड़कर आईपीएल में जाने का फैसला किया है। लगातार दूसरे साल ये दोनों लीग एक ही समय पर हो रही हैं। श्रीलंका के दासुन शनाका पाकिस्तान सुपर लीग से अपना नाम वापस लेने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने लाहौर कलंदर्स की टीम को छोड़कर आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलने का फैसला किया है। राजस्थान ने शनाका को चोटिल सैम करन की जगह पर बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर डेनियल सैम्स लाहौर कलंदर्स में शनाका की जगह लेंगे। ब्लेसिंग मुजरबानी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के साथ आईपीएल का करार पक्का होने के बाद पहले ही पाकिस्तान सुपर लीग से हट चुके हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, 'हम नियमों के अनुसार उन खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

न्यूजीलैंड में नई टी20 प्रतियोगिता 'एनजेड20' को मिली मंजूरी

सुपर स्मैश की जगह हो सकता है आयोजन

एजेंसी (हि.स.)
वेलिंगटन

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने प्रस्तावित नई टी20 प्रतियोगिता 'एनजेड20' को देश की प्रमुख घरेलू टी20 प्रतियोगिता बनाने की दिशा में प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के बाद बोर्ड अब प्रतियोगिता के संचालन, अधिकार वितरण और व्यावसायिक व्यवस्था जैसे पहलुओं पर काम करेगा।

फोटोः हि.स.

न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार, यह कदम देश की घरेलू टी20 व्यवस्था को नया रूप देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके लागू होने पर वर्तमान सुपर स्मैश प्रतियोगिता की जगह 'एनजेड20' ले सकती है। सुपर स्मैश की शुरूआत पुरुष वर्ग में 2005-06 और महिला वर्ग में 2007-08 में हुई थी। नई प्रतियोगिता के साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट मौजूदा संघ-आधारित प्रणाली से हटकर टीम-आधारित व्यवस्था अपनाएगा, जैसा कि दुनिया के कई देशों में प्रचलित है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की अध्यक्ष डायना पुकेटापु-लिंडन ने सोमवार को बताया कि बोर्ड के सामने 'एनजेड20' को स्वतंत्र रूप से आयोजित करने या ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश प्रतियोगिता से जोड़ने का विकल्प था, लेकिन विस्तृत चर्चा के बाद स्वतंत्र प्रतियोगिता को ही उचित माना गया। उन्होंने कहा, बोर्ड ने सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि 21 वर्ष पुरानी सुपर स्मैश प्रतियोगिता को नए रूप में प्रस्तुत करने का यही सही समय है।

इसके लिए व्यापक परामर्श और डेलॉइट की रिपोर्ट सहित कई पहलुओं का अध्ययन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगला चरण 'एनजेड20' के साथ शर्तों को अंतिम रूप देना और सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने यह भी स्पष्ट किया कि नई प्रतियोगिता में महिला क्रिकेट को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि महिला टी20 प्रतियोगिता को समान महत्व और व्यापक पहचान मिल सके। इसके साथ ही क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बनाए रखने पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे देशभर के दर्शक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को करीब से देख सकें। टीमों के स्वामित्व और हिस्सेदारी से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

'विश्व क्षय रोग दिवस: संकल्प से सिद्ध होगा तपेदिक मुक्त भारत का सपना'

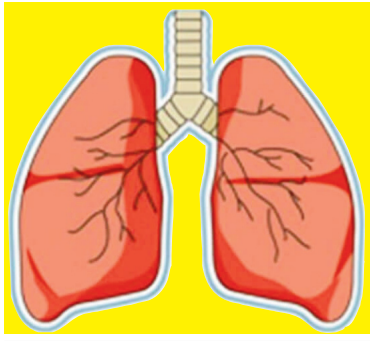

24 MARCH WORLD TUBERECULOSIS DAY

विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन इस वैश्विक महामारी के प्रति जागरूकता फैलाने और इसे समाप्त करने के प्रयासों को तेज करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में से एक है। 'माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस' नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाली यह बीमारी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर दिन हजारों लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवाते हैं, जबकि यह एक उपचार योग्य और रोकथाम योग्य बीमारी है।

इतिहास

विश्व क्षय रोग दिवस का इतिहास 19वीं शताब्दी से जुड़ा है। 24 मार्च, 1882 को डॉ. रॉबर्ट कोच ने बर्लिन में 'तपेदिक के बैक्टीरिया' की खोज की घोषणा की थी। उस समय यूरोप और अमेरिका में हर सात में से एक व्यक्ति की मृत्यु टीबी से हो रही थी। इस खोज के 100 साल बाद, 1982 में 'इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज' ने प्रस्ताव रखा कि 24 मार्च को आधिकारिक तौर पर विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाए। 1996 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे दुनिया भर में एक वार्षिक आयोजन बनाने के लिए अन्य संगठनों के साथ हाथ मिलाया।

महत्व

यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन है। इसका महत्व निम्नलिखित कारणों से है। टीबी के लक्षणों (जैसे 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, बुखार, वजन घटना) के बारे में लोगों को शिक्षित करना। समाज में टीबी के मरीजों के प्रति भेदभाव को खत्म करना ताकि वे खुलकर इलाज करा सकें। सरकारों को इस बीमारी के उन्मूलन के लिए पर्याप्त बजट और संसाधन आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

उद्देश्य

विश्व क्षय रोग दिवस मनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। 2030 तक दुनिया को टीबी मुक्त बनाने के 'सतत विकास लक्ष्यों' को प्राप्त करना। भारत ने इसे समाप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह सुनिश्चित करना कि हर मरीज को समय पर सही जांच (जैसे बलगम जांच या सीबी-नैट मशीन) और मुफ्त दवाएं मिलें। नई वैक्सीन, बेहतर दवाओं और कम समय वाले उपचार पाठ्यक्रमों की खोज के लिए निवेश बढ़ाना। मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का सामना: उन स्थितियों को रोकना जहां दवाएं बैक्टीरिया पर बेअसर हो जाती हैं।

टीबी के लक्षण और बचाव

लेख में पाठकों के लिए यह जानकारी अत्यंत आवश्यक है। लक्षण: लगातार खांसी, रात में पसीना आना, सीने में दर्द और भूख की कमी। बचाव: बच्चों को जन्म के समय का टीका लगवाना, पौष्टिक आहार लेना, और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर मास्क का उपयोग करना।

वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयास

सरकारें अब 'निक्षय पोषण योजना' जैसे कार्यक्रमों के जरिए मरीजों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही हैं ताकि वे बेहतर आहार ले सकें। #टीबी हारेगा, देश जीतेगा# जैसे नारे आज घर-घर में गूँज रहे हैं। विश्व क्षय रोग दिवस हमें याद दिलाता है कि सामूहिक प्रयासों से ही हम इस प्राचीन बीमारी पर विजय पा सकते हैं। यदि समाज का हर नागरिक जागरूक हो और मरीजों का साथ दे, तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया टीबी के साये से पूरी तरह मुक्त होगी।

असम राइफल्स स्थापना दिवस: 'उत्तर-पूर्व के प्रहरी' और भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल को सलाम

असम राइफल्स-वीरता और विरासत का संगम

असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 24 मार्च 1835 को हुई थी। शुरूआत में इसे 'कछार लेवी' के नाम से जाना जाता था। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर-पूर्व भारत के चाय बागानों और बस्तियों की सुरक्षा करना था। समय के साथ इस बल का नाम कई बार बदला गया, जैसे 'असम फ्रंटियर पुलिस', 'असम मिलिट्री पुलिस' और 'पूर्वी बंगाल और असम मिलिट्री पुलिस'। अंततः 1917 में इसका नाम बदलकर 'असम राइफल्स' कर दिया गया।विश्व युद्धों में योगदानः इस बल ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी वीरता का लोहा मनवाया।आजादी के बादः 1962 के भारत-चीन युद्ध से लेकर आतंकवाद विरोधी अभियानों तक, असम राइफल्स ने हमेशा देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है।

उत्तर-पूर्व के प्रहरी

असम राइफल्स को 'उत्तर-पूर्व के प्रहरी' और 'पर्वतीय लोगों के मित्र' कहा जाता है। यह बल म्यांमार सीमा की सुरक्षा के साथ-साथ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और विकास कार्यों में मदद करने का काम करता है। यह भारत का एकमात्र ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसका नियंत्रण दो मंत्रालयों के पास है: प्रशासनिक नियंत्रणः गृह मंत्रालय के पास। परिचालन नियंत्रणः भारतीय सेना (रक्षा मंत्रालय) के पास।

स्थापना दिवस का महत्व

24 मार्च का दिन उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। इस दिन शिलॉन्ग (मुख्यालय) और विभिन्न बटालियनों में परेड, खेलकूद प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

जहां राह कठिन है, वहां हम है

दुर्गम पहाड़ियों से लेकर घने जंगलों तक, असम राइफल्स के जवान न केवल देश की सीमा की रक्षा करते हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर शांति और भाईचारे का संदेश भी देते हैं।

अचीवर्स के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस: सपनों को हकीकत में बदलने वाले जुनून को सलाम

अचीवर्स के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 24 मार्च को उनके उद्देश्य और आत्मविश्वास की मजबूत भावना का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। अचीवर्स वे होते हैं जो लक्ष्य बनाते हैं और निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अचीवर्स किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं चाहे वह कला, विज्ञान, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य या सामाजिक कार्य हो।

अचीवर कौन है

एक अचीवर वह होता है जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होते हैं। उपलब्धि का संबंध आवश्यक रूप से अधिक धन या प्रसिद्धि अर्जित करने से नहीं है, अलग-अलग लोगों के लिए इसका अर्थ अलग-अलग हो सकता है। उपलब्धि सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त करना, शिखर पर चढ़ना, एक नया कौशल या भाषा सीखना, एक किताब लिखना, एक व्यवसाय शुरू करना, एक विशेष कला सीखना, स्वास्थ्य लक्ष्यों तक पहुंचने या किसी अन्य उपलब्धि के रूप में हो सकता है।

क्यों मनाया जाता है

अचीवर्स के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपने चुने हुए क्षेत्र या गतिविधि में कड़ी मेहनत करके एक उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह दिन उद्देश्य से प्रेरित लोगों को स्वस्थ महत्वाकांक्षा, इच्छाशक्ति और स्पष्ट दृष्टि और अनुशासन के साथ मनाता है। यह दिन अचीवर्स के दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और अनुकूलन क्षमता को उजागर करने पर केंद्रित है जो उन्हें अन्य लोगों से अलग करता है। यह दिन लक्ष्य निर्धारित करने और उन तक पहुंचने के प्रयास के महत्व पर प्रकाश डालता है। कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है यदि वे पर्याप्त प्रयास करें तो।

कैसे मनाया जाता है

अचीवर्स के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। दुनिया भर के कुछ स्कूल इस दिन अपने अध्ययन के क्षेत्र में अनुकरणीय उपलब्धियां हासिल करने वाले छात्रों को पुरस्कृत करते हैं। इस दिन उन कर्मचारियों को भी पहचान की जाती है जिन्होंने उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। सभी लोग पहले लक्ष्य निर्धारित करके अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि दिवस मना सकते हैं, जो वे एक समयरेखा के साथ चाहते हैं। लोग पिछली उपलब्धियों का जश्न भी मना सकते हैं और दूसरों को भी सार्वजनिक मंचों पर साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। लोग #InternationalDayForAchievers हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों और लक्ष्य को साझा कर सकते हैं। यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिन समय का सामना करना पड़ता है और उन्हें थोड़ी सी मजबूत प्रेरणा की आवश्यकता हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त करने की शक्ति रखता है, बस उसे कभी-कभी याद दिलाना पड़ता है।

भारत के जाने-माने ट्रांसप्लांट सर्जनों का सालाना सम्मेलन संपन्न

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

अंग प्रत्यारोपण चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है – और साथ ही, सबसे कम समझी जाने वाली उपलब्धियों में से भी एक। लाखों भारतीय जो अंग फेल होने की अंतिम अवस्था में जी रहे हैं, उनके लिए ट्रांसप्लांट सिर्फ. एक इलाज नहीं, बल्कि एक दूसरी ज़िंदगी है। फिर भी, ट्रांसप्लांट विज्ञान, अंग दान, और इन कार्यक्रमों को चलाने वाले जटिल क्लिनिकल सिस्टम के बारे में आम लोगों में जागरूकता बहुत कम है। नीति-निमार्ता भी मरीजों की बढ़ती संख्या और अंग फेल होने की गंभीर स्थिति से अवगत हैं, लेकिन पूरे देश में मृत्यु के बाद अंग दान की प्रक्रिया शुरू करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ठीक इसी कमी को दूर करने के लिए 'इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन्स' जैसे संगठन काम कर रहे हैं – वे न केवल विशेषज्ञों के बीच इस विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि उन विभिन्न केंद्रों के साथ मिलकर कार्यप्रणाली भी विकसित कर रहे हैं, जिन्होंने अंग दान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

'लाइव ऑपरेटिव डेमोंस्ट्रेशन' (प्रत्यक्ष शल्य-क्रिया प्रदर्शन) इस सम्मेलन का मुख्य वैज्ञानिक आकर्षण था। इन सत्रों में लैप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टॉमी, पारंपरिक ओपन सर्जरी और रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तथा लैप्रोस्कोपिक डोनर हेपेटेक्टॉमी जैसे विषयों को शामिल किया गया – जो पारंपरिक ओपन सर्जरी से लेकर अत्याधुनिक रोबोटिक ट्रांसप्लांटेशन तक की विभिन्न तकनीकों का एक व्यापक प्रदर्शन था। डॉ. अरुण कपूर और डॉ. हर्षा जौहरी द्वारा संचालित तथा जाने-माने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की उपस्थिति से समृद्ध इन ऑपरेटिव सत्रों में परिणामों के आँकड़ों, तकनीकी विविधताओं और संस्थागत कार्यप्रणालियों पर जीवंत चचाएँ हुईं।

इस सम्मेलन का एक मुख्य आकर्षण 'अग्नाशय प्रत्यारोपण' पर आयोजित सत्र था। इस सत्र में डॉ. संजय बदाडा ने टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित मरीजों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला; उन्होंने बताया कि जब इन मरीजों की किडनी भी फेल हो जाती है, तो उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम रह जाती है। हालाँकि, अग्नाशय प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू होने के बाद अब परिणामों में जबरदस्त सुधार आया है, और अब मरीज 10 साल से भी अधिक समय तक जीवित रह पा रहे हैं। इस सत्र में अग्नाशय प्रत्यारोपण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें अग्नाशय निकालने की प्रक्रिया , 'बेंच सर्जरी' और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया का वीडियो प्रदर्शन मुख्य रूप से शामिल था – इसके साथ ही, 'पेरिऑपरेटिव मैनेजमेंट' (सर्जरी के दौरान और उसके बाद की देखभाल) और अंग आवंटन नीति पर भी पैनल चचाएँ आयोजित की गईं। छोटी आंत का ट्रांसप्लांट, आइलेट सेल ट्रांसप्लांट, और टाइप 1 डायबिटीज तथा अंतिम चरण के अंग फेलियर वाले मरीजों के लिए इलाज के विकल्पों ने इस कार्यक्रम की पहुँच को पूरे चिकित्सीय क्षेत्र तक बढ़ा दिया। अमेरिका के डॉ. बाला ने आइलेट सेल ट्रांसप्लांट के बेहतरीन नतीजों के बारे में बताया, जिनसे डायबिटीज ठीक हो गई और मरीजों को दो दशकों तक इंसुलिन पर निर्भर नहीं रहना पड़ा।

एक और बहुत सराही गई चर्चा नॉर्मोथर्मिक मशीन के बारे में थी, जिसके जरिए पीजीआई चंडीगढ़ में स्थापित अत्याधुनिक तकनीक की मदद से, इस्तेमाल न की जाने वाली किडनियों को बचाया जा सकता है और उनका सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। 20 मार्च की शाम को हुआ औपचारिक उद्घाटन समारोह एक ऐतिहासिक अवसर था। पीजीआई के निदेशक, प्रो. विवेक लाल ने पीजीआई में एक अलग ट्रांसप्लांट केंद्र स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता से वहाँ मौजूद लोगों में जोश भर दिया – इस तरह उन्होंने ट्रांसप्लांट समुदाय की लंबे समय से चली आ रही एक इच्छा को संस्थागत रूप दिया। उन्होंने भारत में ट्रांसप्लांट शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपने दूरदर्शी प्रयासों के लिए प्रो. आशीष शर्मा के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त किया, और यह स्वीकार किया कि क्ऴ्ळर जैसे मंचों के माध्यम से बोए गए बीज आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विशेषज्ञता को आकार देंगे।

रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी विभाग के दो सीनियर रेजिडेंट, डॉ. कपिल बजाज और डॉ. प्रणीत रेड्डी को उनकी संबंधित श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने ऐसी नवीन तकनीकों पर डेटा प्रस्तुत किया, जो डायलिसिस पर निर्भर किडनी फेलियर के मरीजों को पेश आ रही समस्याओं को हल करती हैं।

राज्यपाल ने म्यूज़ियम ऑफ ट्रीज में भगत सिंह के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के राज्यपाल एवं यू.टी. चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज म्यूज़ियम ऑफ ट्रीज, गांव दरिया, चंडीगढ़ का दौरा कर शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पर आनुवंशिक रूप से तैयार बेर के पौधे को जल देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मूल वृक्ष भगत सिंह ने वर्ष 1917 में पाकिस्तान के फैसलाबाद स्थित अपने पैतृक गांव बांगे में लगाया था, उस समय उनकी आयु मात्र दस वर्ष थी।

राज्यपाल ने शहीद भगत सिंह के साहस और आदर्शों को नमन किया। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह आज भी अपने देशभक्ति, दृढ़ विश्वास और निर्भीकता से पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने युवाओं से उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए समर्पण और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। राज्यपाल ने म्यूज़ियम ऑफ ट्रीज, चंडीगढ़ द्वारा वैज्ञानिक तरीकों से ऐतिहासिक महत्व के वृक्षों को संरक्षित करने के प्रयासों की सराहना की और राष्ट्रीय नायकों से जुड़ी विरासत के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से भगत सिंह से प्रेरणा लेकर पर्यावरण और राष्ट्र की विरासत को संरक्षित करने में योगदान देने का आह्वान किया। श्री डी.एस. जसपाल, सेवानिवृत्त क्ऴ्अर एवं म्यूज़ियम ऑफ ट्रीज के संस्थापक, ने महत्वपूर्ण वृक्षों के आनुवंशिक क्लोनिंग के माध्यम से आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने में संग्रहालय की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत की विरासत केवल स्मारकों में ही नहीं, बल्कि वृक्षों में भी जीवित है और इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना आवश्यक है। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक प्रताप सिंह भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान संग्रहालय टीम ने महत्वपूर्ण और पवित्र वृक्षों के आनुवंशिक रूप से संरक्षित प्रतिरूपों के संरक्षण संबंधी अपने कार्यों की जानकारी साझा की।

शहीदी दिवस पर एनएसएस स्वयंसेवकों ने अपनी फौज को जाने कार्यक्रम के माध्यम से दी शहीदों को श्रद्धांजलि

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

सेक्टर -1 स्थित गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के चल रहे सात दिवसीय कैंप के चौथे दिन सोमवार को शहीदी दिवस के अवसर पर ज्ञान सेतु थिंक टैंक द्वारा चंडीगढ़ सिटिजन्स फाउंडेशन के सहयोग से ₹अपनी फौज को जाने₹ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर चंडीमंदिर स्थित भारतीय सेना के पश्चिमी कमान द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए कॉलेज के एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया।

यह पहल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. कटियार, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम तथा चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों ने नवनिर्मित युद्ध स्मारक पर जाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा आर्मी म्यूजियम का अवलोकन कर भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास और परंपराओं से परिचित हुए। उन्हें सेना के पश्चिमी कमान एवं ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक प्रेरणादायक फिल्म भी दिखाई गई। साथ ही आधुनिक सैन्य उपकरणों एवं ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन भी कराया गया, जिसने विद्यार्थियों को अत्यंत प्रभावित किया। हाथों में तिरंगा थामे एनएसएस स्वयंसेवकों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहें, इंकलाब जिंदाबाद एवं भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से वातावरण को देशभक्ति से ओत-प्रोत करते हुए भव्य तिरंगा रैली निकाली। रैली का उद्देश्य युवाओं में शहीदों के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रगाढ़ करना था। सात दिवसीय कैंप के अंतर्गत आयोजित इस गतिविधि का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हुए उन्हें नागरिक योद्धा के रूप में तैयार करना था।

आयकर विभाग ने शहीदी दिवस का आयोजन किया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, श्री अशोक कुमार सरोहा के संरक्षण में आयकर विभाग द्वारा एनआईटीटीटीआर सभागार, सेक्टर-26, चंडीगढ़ में शहीदी दिवस का गरिमामय आयोजन किया गया।इस अवसर पर विभाग द्वारा क्षेत्र के उन शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर अनुज राजपूत, कैप्टन सतीश चंद्र सहगल, कैप्टन रमेश चंदर शर्मा, लांस नायक हरचंद तथा लांस नायक विक्रम सिंह के अदम्य साहस एवं बलिदान को गहरी श्रद्धा एवं कृतज्ञता के साथ स्मरण किया गया। कार्यक्रम में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकूला एवं शिमला, सुश्री विदिशा कालरा, आई.आर.एस.; महानिदेशक आयकर (अन्वेषण), सुश्री वत्सला झा, आई.आर.एस.; मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर, डॉ. जी. एस. फणी किशोर, आई.आर.एस.; तथा मुख्य आयकर आयुक्त (ओएसडी), सुश्री कोमल जोगपाल, आई.आर.एस. शामिल थीं।

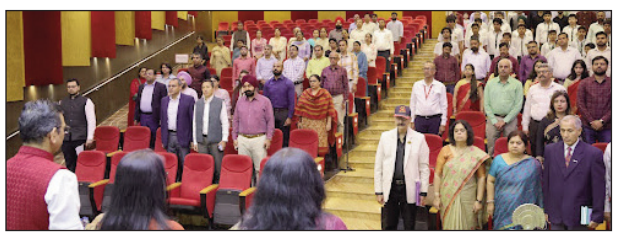

शहीदों के परिजनों को विभाग की ओर से सम्मान एवं कृतज्ञता के प्रतीक स्वरूप विशेष रूप से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत सतलुज पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा देशभक्ति गीतों की समूह एवं एकल प्रस्तुतियाँ दी गईं। इसके अतिरिक्त, चंडीगढ़ के प्रख्यात नाट्य समूह मंथन द्वारा भगत सिंह एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित एक प्रभावशाली नाट्य प्रस्तुति दी गई, जिसने उपस्थित दर्शकों को भावविभोर कर दिया। इस अवसर को चिह्नित करते हुए, पूर्वाह्न में आयकर भवन, चंडीगढ़ एवं पंचकूला में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। ये शिविर पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़, नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट्स एंड एक्टिविस्ट्स (निफा), श्री राकेश कुमार सांगड़ के नेतृत्व में, तथा श्री शिव कांवड़ महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किए गए। कार्यक्रम का सफल संचालन सुश्री पूनम राय, आई.आर.एस. द्वारा किया गया तथा इसमें विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। यह आयोजन राष्ट्रभक्ति एवं बलिदान की भावना को समर्पित एक गरिमामय एवं स्मरणीय श्रद्धांजलि के रूप में संपन्न हुआ।

पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता से करें जनगणना कार्य का निर्वहन : डा. ललित जैन

सिटी दर्पण संवाददाता
रेवाड़ी

जनगणना कार्य निदेशक हरियाणा डा. ललित जैन ने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य को गंभीरता से लें और आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा में सभी तैयारियां पूर्ण करें।

सोमवार को जिला सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में डा. ललित जैन ने जनगणना 2027 की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि आगामी जनगणना पूर्णतः डिजिटल माध्यम से करवाई जाएगी, जिससे कार्य में पारदर्शिता, गति और सटीकता सुनिश्चित होगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है, इसलिए जनगणना कार्य के लिए नियुक्त किए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि यह कार्य देश के विकास की आधारशिला है, इसलिए आंकड़ों की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करें और आपसी तालमेल बनाए रखें।

बैठक में डीसी अभिषेक मीणा ने जिला में जनगणना को लेकर अब तक की गई तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा ड्यूटी निर्धारण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा, डिजिटल जनगणना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। डीसी ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य को समय पर पूरा किया जाएगा।

जनगणना कार्य निदेशक हरियाणा डा. ललित जैन ने कहा कि जिला में लोगों को जनगणना जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य को लेकर जागरूक किया जाए। जनगणना कार्य के दौरान पहुंचे जाने वाले सवालों की सही जानकारी देना और इसकी विश्वनीयता के बारे में आमजन को जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके लिए विद्यालयों में जनगणना कार्य को लेकर भाषण और प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित कर विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों को जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

बैठक में एसडीएम रेवाड़ी सुरेश कुमार, एसडीएम कोसली विजय कुमार यादव, एसडीएम बावल मनोज कुमार, सीटीएम जितेंद्र कुमार, जिला कोऑर्डिनेटर दीपक कुमार और ट्रेनिंग नोडल अधिकारी अमित कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़ के निवासियों के बीच स्वस्थ जीवन शैली, यानी शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए वॉकथॉन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सीएमई की शुरूआत कैरों ब्लॉक, पीजीआई से सुखना झील तक एक वॉकथॉन के साथ होगी, जो हृदय रोगों की रोकथाम में शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व का प्रतीक है। इस वॉकथॉन का उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवरों, छात्रों और आम जनता को ठउऊ के जोखिम को कम करने में दैनिक व्यायाम और व्यवहारिक बदलावों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने में शामिल करना है। वैज्ञानिक सत्रों में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी, जिसमें भारत में हृदय रोगों की बदलती महामारी विज्ञान—जिसमें पश्चात युग में सीखे गए सबक भी शामिल हैं—शामिल हैं; जोखिम मूल्यांकन, इमेजिंग और भविष्य कहनेवाला मॉडलिंग में प्रगति; स्वास्थ्य कार्यबल की चुनौतियों को संबोधित करना, विशेष रूप से हृदय संबंधी नर्सिंग के क्षेत्र में; उभरती और बनी रहने वाली चुनौतियाँ, जैसे कि नए जोखिम कारक, मातृ हृदय स्वास्थ्य और आमवाती हृदय रोग; समय पर और प्रभावी हस्तक्षेप के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों और देखभाल नेटवर्क को मजबूत करना; और कार्डियक पुनर्वास, हाइब्रिड देखभाल मॉडल और हृदय विफलता के प्रबंधन में नवाचार। इन चचाओं का उद्देश्य विविध स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटना है। पीजीआई के निदेशक प्रो. विवेक लाल, पीजीआई के डीन प्रो. आर.के. राथो और वळ के ऊ्ऴर डॉ. सुमन सिंह को उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया है। सीएमई का एक मुख्य हिस्सा सीवीडी की रोकथाम और नियंत्रणः उभरते क्षेत्र पर एक पैनल चर्चा होगी, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ और राज्य कार्यक्रम अधिकारी शामिल होंगे।

संक्षिप्त-समाचार

आरती राव ने किए माता मनसा देवी के दर्शन

पंचकूला। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने चैत्र नवरात्र के पांचवें दिन आज पंचकूला के एतिहासिक माता मनसा देवी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और महामाई का आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का माता मनसा देवी मंदिर पहुँचने पर प्रशासन और श्राइन बोर्ड की और से स्वागत किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निशा यादव, बोर्ड की सचिव श्रीमती शारदा प्रजापति, सिविल सर्जन डॉ मुक्ता कुमार, डिप्टी एसएमओ डॉ विकास गुप्ता एवं अनेक अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे ।

राजकीय महाविद्यालय कालका में 'बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट' प्रतियोगिता का सफल आयोजन

पंचकूला । श्रीमती अरुणा आसफ अली राजकीय महाविद्यालय कालका की प्राचार्या डॉ. गीता सुखीजा के नेतृत्व में गृह विज्ञान विभाग द्वारा 'बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट' प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना और उन्हें बेकार पड़ी चीजों का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रेरित करना था, ताकि हम एक सतत जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण को बचाने की दिशा में अपना योगदान दे सकें। इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन का श्रेय गृह विज्ञान विभाग की डॉ. सोनाली गुप्ता को जाता है, और इस कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका डॉ. बिंदु शर्मा, डॉ. नवनीत नैन्सी और डॉ. नीरू कंबोज ने निभाई। प्रतियोगिता में बी.ए. द्वितीय वर्ष की छात्रा प्राची ने प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि बी.ए. प्रथम वर्ष की छात्रा आकांक्षा ने द्वितीय पुरस्कार और बी.ए. प्रथम वर्ष की छात्रा रितु ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया।

यूनोइया 2026 के दौरान पेक छात्रों ने मैजिक बाउल क्विज में पहला स्थान हासिल किया

चंडीगढ़। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), चंडीगढ़ के छात्रों ने यूनोइया 2026 के अंतर्गत आयोजित प्रतिष्ठित मैजिक बाउल क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे यह एक अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक और बौद्धिक रूप से समृद्ध आयोजन बन गया। पेक की विजेता टीम में राघव अरोड़ा (द्वितीय वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) और नमन वासुदेव (द्वितीय वर्ष, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग) शामिल थे। रैपिड-फायर प्रारूप में आयोजित इस क्विज में सामान्य ज्ञान, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति जैसे विविध विषयों पर प्रतिभागियों की परख की गई। क्षेत्र के प्रतिभाशाली प्रतिभागियों के बीच पीईसी टीम ने अपने उत्कृष्ट ज्ञान, त्वरित सोच और बेहतरीन टीमवर्क का परिचय देते हुए सभी चरणों में शानदार प्रदर्शन किया। कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टीम ने प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। संस्थान ने छात्रों को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी और कॉलेज का गौरव बढ़ाने के लिए उनकी सराहना की।

मोरनी से माता समलौथा देवी तक 18 किलोमीटर ट्रैक, छात्राओं ने दिखाया उत्साह

पंचकूला। हरियाणा सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आज मोरनी से माता समलौथा देवी तक लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैक आयोजित किया गया। यह 3 दिवसीय ट्रैकिंग कार्यक्रम हरियाणा विश्वविद्यालयों की छात्राओं के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छात्राएं बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं। इस ट्रैकिंग कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से उन्हें प्रकृति के प्रति जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण तथा साहसिक गतिविधियों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है। युवा कल्याण संयोजक नरेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा युवा कल्याण योजना के अंतर्गत पूर्व में भी कई ट्रैकिंग अभियानों का सफल आयोजन किया जा चुका है और वर्तमान में भी ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम वर्क की भावना का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम छात्राओं को न केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनाते हैं, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं।

समागम | **निरंकारी संत समागम ने जगाई मानव एकता व प्रेम की ज्योति**

निरंकार को जानकर प्रेम, सेवा और समर्पण से जीवन को सार्थक बनाएं: निरंकारी सतगुरु माता जी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/पंचकुला/मोहाली/कानपुर,

निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद एवं आदरणीय निरंकारी राजपिता जी की गरिमामयी उपस्थिति में रेलवे ग्राउंड, पराग डेयरी, कानपुर में उत्तर प्रदेश प्रादेशिक निरंकारी संत समागम का भव्य, सुव्यवस्थित एवं अत्यंत प्रेरणादायी आयोजन संपन्न हुआ। जहाँ आध्यात्म, प्रेम, अनुशासन, श्रद्धा, समर्पण और आध्यात्मिक चेतना का अद्वितीय संगम देखने को मिला।

उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर इस आयोजन को एक विराट आध्यात्मिक पर्व का स्वरूप दिया। समागम स्थल को एक सुव्यवस्थित टेंट नगरी के रूप में विकसित किया गया, जहाँ स्वच्छता, अनुशासन और आध्यात्मिक प्रेम का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। श्रद्धालु एक परिवार की भांति आपसी प्रेम, एकत्व, शांति और सद्भावना के साथ एकत्रित हुए।

समागम से पूर्व निरंकारी यूथ फोरम (एन.वाई.एफ.) द्वारा खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सुंदर आयोजन किया गया। युवाओं ने क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लेकर टीम भावना, अनुशासन और सहयोग जैसे मूल्यों को आत्मसात किया। साथ ही, निरंकारी यूथ सिम्पोजियम (एन.वाई.एस.) के माध्यम से युवाओं को आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन एवं अभिव्यक्ति का मंच प्रदान किया गया।

समागम के दौरान ह्लछ: तत्व (ग्र७ ए'ीिल्ल३२)ह्व विषय पर आधारित स्किट, गीत एवं पैनल चर्चा के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि आध्यात्मिकता केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सार्थक शैली है। गीत, प्रवचन, कविताओं एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से श्रद्धालुओं ने अपने भक्ति भाव को व्यक्त किया, जिससे सेवा, प्रेम और मानवीय मूल्यों का संदेश जन-जन तक पहुँचा।

अपने पावन आशीर्वचनों में सतगुरु माता जी ने फरमाया कि परमात्मा हमारे जीवन में विचारों, भावनाओं और रचनाओं के माध्यम से प्रकट होता है। यह जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संसार के लिए एक सुंदर बलिदान बनने का अवसर है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन का उद्देश्य प्रेम, दया, करुणा, विनम्रता और सहनशीलता जैसे गुणों को अपनाना है।

तितली के उदाहरण द्वारा माता जी ने समझाया कि जैसे तितली परिवर्तन के बाद सुंदर बनती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उसे श्रेष्ठ बनाना चाहिए। उन्होंने प्रेरित किया कि हम बिच्छू की तरह डसने वाले नहीं, बल्कि भलाई करने वाले बनें—हमारे कर्म दिखावे से रहित, सच्चाई और नेकी से भरपूर हों।

माता जी ने कहा कि सच्ची भक्ति और सत्संग से मन की पीड़ा दूर होती है और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जब मनुष्य निरंकार को प्राथमिकता देता है, तब वह जीते-जी मुक्ति का अनुभव करता है। सेवा, सुमिरन और सत्संग को जीवन का आधार बताते हुए उन्होंने समर्पण भाव से जीवन जीने की प्रेरणा दी।

समागम का समापन श्रद्धालुओं के हृदय में सत्य, एकता और मानवता के मार्ग पर दृढ़ता से चलने के संकल्प के साथ हुआ। इस दिव्य आयोजन ने सभी के जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक जागरूकता का संचार किया।

अंत में निरंकारी मिशन की ओर से प्रशासन एवं सभी विभागों का इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में दिए गए सहयोग हेतु हृदय से आभार व्यक्त किया गया।